https://www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

'मोदी सरकार की उत्तर-पूर्व की विकास की नीति पर मुहर'

वर्ष-13, अंक-06 16-31 मार्च, 2018 (पाक्षिक) ₹20

'सबका साथ, सबका विकास' की जीत

पूर्वोत्तर में भाजपा की ऐतिहासिक जीत | कृषि विकास से भारत का विकास | भ्रम और भय फैलाना कांग्रेस की नीति बन गई है

अगरतला, त्रिपुरा में पहली भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण के बाद जनाभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री बिप्लब कुमार देब सहित अन्य नेतागण

कोहिमा, नगालैंड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक ग्रुप फोटो में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, मुख्यमंत्री श्री नेफ्यू रियो, उप-मुख्यमंत्री श्री वाई पट्टन और अन्य गणमान्य व्यक्ति

मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मुहैया कराने हेतु 'नमो योजना सहायता केंद्र' का उद्घाटन करने के बाद दिल्ली में लोगों को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

शपथ ग्रहण के बाद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह का अभिवादन करते मेघालय के नए मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमा

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com

वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 पूर्वोत्तर में भाजपा की ऐतिहासिक जीत

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के नेतृत्व में एक के बाद एक राज्यों में पार्टी जीत का परचम फहरा रही है। हाल ही में उत्तर-पूर्व के तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे भाजपा में नई ऊर्जा भरने वाले रहे। त्रिपुरा, नगालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव में...

वैचारिकी

चिति है हमारे राष्ट्र का प्राण 17

श्रद्धांजलि

ब्रह्मलीन हुए जगदगुरु जयेंद्र सरस्वती 20

लेख

कृषि विकास से भारत का विकास 21

भ्रम और भय फैलाना कांग्रेस की नीति बन गई है 24

अन्य

कोनराड संगमा ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ 13

तीसरी तिमाही (अक्तूबर से दिसंबर तक) में जीडीपी की वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत 14

राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी 19

मंत्रिमंडल ने भगौड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 को मंजूरी दी 26

केंद्र सरकार किसानों की भलाई के लिए कटिबद्ध है : अमित शाह 28

'हर मोर्चे पर विफल है कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार' 30

'भाजपा सरकार देश के ओबीसी समाज और पिछड़े समाज के कल्याण के लिए कटिबद्ध' 31

स्थायी स्तंभ

सोशल मीडिया से 04

पत्र-पत्रिकाओं से 33

स्फुट विचार 33

संगठनात्मक गतिविधियां

10 त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देब ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ

भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री बिप्लब कुमार देब ने 9 मार्च को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री...

12 नेफ्यू रियो ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

नगालैंड में 8 मार्च को भाजपा गठबंधन की सरकार बनी। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव...

सरकार की उपलब्धियां

15 जनवरी, 2018 में आठ कोर उद्योगों की वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत

आठ कोर उद्योगों का संयुक्त सूचकांक जनवरी, 2018 में 133.1 अंक रहा, जो जनवरी, 2017...

16 पीएमएवाई (शहर) के तहत शहरी गरीबों के लिए 1,28,509 किफायती घर मंजूर

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

राष्ट्रीय पोषण मिशन एक महत्वपूर्ण पहल है जो कुपोषण और कमजोर नवजात बच्चों में कमी लाता है। यह बच्चों, महिलाओं और युवतियों में एनीमिया को कम करने और ठिगने बच्चों की संख्या में कमी लाता है।

@AmitShah

नोटबंदी के दौरान जब पूरा देश एकजुट होकर भ्रष्टाचार और कालेधन के विरुद्ध अभियान को आगे बढ़ा रहा था, तब कांग्रेस गरीबों की आड़ में कालेधन का समर्थन कर देश में भ्रम और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही थी। नोटबंदी को लेकर भी कांग्रेस के सारे आरोप गलत साबित हुए हैं।

@RadhamohanBJP

मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। एक नया भारत बनाने की ओर। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना से अब महंगी दवाईयां सस्ती दरों में मिल रही है।

facebook

महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। इनके विरुद्ध हिंसा रोकने और सामुदायिक पुलिसिंग के क्षेत्र में कार्य योजना बनाने के लिए आज विधानसभा में मध्यप्रदेश पुलिस और शैफील्ड हैलम विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम के मध्य करार हुआ। — **शिवराज सिंह चौहान**

अन्नदाता के हितों को ध्यान में रखते हुए इस बार के मूल बजट में लघु एवं सीमांत किसानों के सहकारी बैंकों के 30 सितम्बर, 2017 तक के अल्पकालीन फसली ऋण में से 50 हजार रुपये तक के कर्ज माफी की घोषणा की थी। इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए राजस्थान वित्त एवं विनियोग विधेयकों पर चर्चा के बाद लघु एवं सीमांत किसानों के साथ-साथ सहकारी बैंकों के सभी श्रेणी के किसानों को भी 50 हजार रुपये तक के बकाया अल्पकालीन फसली ऋण को लघु काश्तकारों के लिए निर्धारित कृषि जोत के अनुपात में, ऋण को एक बारीय माफ करने की सौगात दी। इसके अलावा किसान भाइयों को VCR से हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कृषि कनेक्शनों की समस्त लंबित VCR की मूल राशि का 50% से घटाकर मात्र 10%, 30 जून 2018 तक जमा करने पर निस्तारित करने का निर्णय हमने लिया है। — **वसुंधरा राजे**

राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास की जीत

3 मार्च 2018 को जैसे–जैसे वोट गिने जा रहे थे, यह स्पष्ट होता जा रहा था कि लोगों ने भाजपा एवं इसके सहयोगी दलों के पक्ष में ऐतिहासिक जनादेश दिया है। सबसे बड़ी खबर त्रिपुरा से आई, जहां 25 वर्षों से अजेय समझा जाने वाला कम्युनिस्टों का गढ़ ढह गया। यह मात्र एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि वैचारिक विजय है जिससे इस जनादेश ने राष्ट्रवाद, सुशासन एवं विकास की पताका को उत्तर–पूर्व के आकाश में बुलन्दी से फहरा दिया। लम्बे समय के कम्युनिस्ट शासन में लोग ठगा महसूस कर रहे थे तथा त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। नगालैंड में भी एनडीए सरकार बनाने में सफल रहा तथा भाजपा को 12 सीटों पर सफलता प्राप्त हुई। मेघालय में भी कांग्रेस की सीटें भारी संख्या में घटी और साथ ही वह सत्ता से बाहर हो गई। परिणामस्वरूप एनडीए गठबंधन, जिसमें भाजपा भी भागीदार है, की सरकार मेघालय में भी बन गई। ऐसा पहली बार हुआ है कि उत्तर–पूर्व के आठ में से सात राज्यों में भाजपा एवं इसके सहयोगियों की सरकार है। यह वास्तव में भाजपा के कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी है जबकि पूरा उत्तर–पूर्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आशा एवं विश्वास से देख रहा है। इस पूरे क्षेत्र को दशकों की उपेक्षा एवं पिछड़ापन से निकालकर विकास के रास्ते पर तेजी से लाना पड़ेगा।

उत्तर–पूर्व की जनता ने 'सबका–साथ, सबका–विकास' तथा 'एक भारत–श्रेष्ठ भारत' की अवधारणा को पुरजोर समर्थन दिया है। उत्तर–पूर्व के जो राज्य कांग्रेस–कम्युनिस्ट शासन में उपेक्षा का दंश सहते हुए विकास की दौड़ में पीछे रह गये, वहां के लोगों ने इस क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किये जा रहे विशेष प्रयासों को जबरदस्त जनादेश दिया है।

जहां कम्युनिस्टों को त्रिपुरा में जनता ने पूरी तरह से धूल चटाया, वहीं त्रिपुरा एवं नगालैण्ड में कांग्रेस का सफाया हो गया। मेघालय में कांग्रेस की हार हुई और इसकी जगह पर एक नई सरकार ने शपथ ली। आज जब कम्युनिस्ट देश की राजनीति के हाशिये पर पहुंच गये हैं, कांग्रेस भी इनसे पीछे नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो राष्ट्रीय हित के खिलाफ बोलने में इन दोनों के बीच कड़ी प्रतियोगिता हो रही है। कांग्रेस ने देश पर लंबे समय तक शासन किया, इसकी सरपरस्ती में कम्युनिस्टों ने भी पिछले दरवाजे से सत्ता का स्वाद चखा है। एक ओर कांग्रेस गैर–जिम्मेदाराना तरीके से सत्ता–केन्द्रित वंशवादी राजनीति चलाती रही, वहीं कम्युनिस्ट बिना किसी जिम्मेदारी के सत्ता–सुख भोगते रहे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस सत्य को बिना स्वीकार किए अब भी ये घमंड में जी रहे हैं तथा देश की आंखों के तारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर भी प्रहार करने से नहीं चूकते। देश की जनता चुनाव–दर–चुनाव इन्हें हार पर हार दिलाकर सबक सिखा रही है। पर शायद ये यह नहीं समझ पा रहे कि इन पर न तो जनता का विश्वास है और न ही इनके पास देश के लिए कोई प्रामाणिक कार्यक्रम। इनके पास केवल नकारात्मक भाजपा–विरोधी और मोदी–विरोधी मुद्दा है, जो न तो उनकी पार्टी न ही देश में कोई सकारात्मक ऊर्जा भर सकती है। कांग्रेस–कम्युनिस्ट की नकारात्मकता का स्वरूप अब एक भस्मासुर की तरह हो चुका है जो स्वयं उनके लिये ही विनाशकारी बनता जा रहा है।

उत्तर–पूर्व की जनता ने 'सबका–साथ, सबका–विकास' तथा 'एक भारत–श्रेष्ठ भारत' की अवधारणा को पुरजोर समर्थन दिया है। उत्तर–पूर्व के जो राज्य कांग्रेस–कम्युनिस्ट शासन में उपेक्षा का दंश सहते हुए विकास की दौड़ में पीछे रह गये, वहां के लोगों ने इस क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किये जा रहे विशेष प्रयासों को जबरदस्त जनादेश दिया है। प्रधानमंत्री की इस क्षेत्र के लिए 'अष्ट लक्ष्मी' की अवधारणा तथा सुशासन एवं विकास के नए युग के प्रारम्भ के लिए उठाए गए ठोस कदमों से जनता अब कदम-से-कदम मिलाकर चल पड़ी है। भाजपा के लिये भारी मतदान कर जनता ने 2013 में 1.54 प्रतिशत मत की तुलना में इस बार भाजपा गठबंधन को 50 प्रतिशत से भी अधिक मत त्रिपुरा में दिया तथा नगालैंड में पार्टी पहली बार 12 सीटें प्राप्त करने के सफल रही। राजनैतिक विश्लेषकों को यह चमत्कार से कम नहीं लग रहा। कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत, निरंतर संघर्ष और बलिदान के साथ–साथ केंद्र सरकार के विकास कार्य से यह चमत्कारिक विजय संभव हुआ है। आज जबकि उत्तर–पूर्व में लोकतंत्र की विजय हुई है और विकास अपने कदम बढ़ा रहा है, इस क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव के लिये जनता बधाई की पात्र है। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

पूर्वोत्तर में भाजपा की ऐतिहासिक जीत

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के नेतृत्व में एक के बाद एक राज्यों में पार्टी जीत का परचम फहरा रही है। हाल ही में उत्तर-पूर्व के तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे भाजपा में नई ऊर्जा भरने वाले रहे। त्रिपुरा, नगालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इतिहास रच दिया। त्रिपुरा में वाममोर्चा को भाजपा ने कड़ी शिकस्त दी। नगालैंड और मेघालय में भी भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं, कांग्रेस त्रिपुरा और नगालैंड में खाता तक नहीं खोल पाई। इस जीत के साथ अब भाजपा नेतृत्व वाले राजग गठबंधन की 21 राज्यों, जो देश की 70 प्रतिशत आबादी है, में सरकार बन गई है।

त्रिपुरा : त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 25 साल से सत्तासीन वाम मोर्चा को कड़ी शिकस्त देते हुए ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। भाजपा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 35 सीटों पर जीत दर्ज की एवं इसकी सहयोगी पार्टी इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा को 8 सीटें मिलीं। वहीं, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को 16 सीटों से संतोष करना पड़ा। भाजपा के लिए यह जीत बहुत महत्त्वपूर्ण है। विदित हो कि 2013 के चुनाव में भाजपा को सिर्फ 1.54 प्रतिशत मत मिले थे और एक भी सीट पर सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। पांच साल बाद यानी 2018 में भाजपा को अपने दम पर 43 प्रतिशत मत और 35 सीटें मिलीं। माकपा को करीब सात प्रतिशत मत और 33 सीटों का नुकसान हुआ।

मेघालय : प्रदेश में एनपीपी की अगुवाई में भाजपा के समर्थन से सरकार बनी। मेघालय विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की। नेशनल पीपुल्स पार्टी ने 19 सीटें जीती। कांग्रेस को 21 सीटें मिलीं। वहीं, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी ने 6, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 4, हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 2, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 1 एवं खुन हिनीवट्रेप नेशनल अवेकनिंग मूवमेंट ने 1 स्थान पर जीत हासिल की। निर्दलीय 3 स्थानों पर विजयी रहे।

नगालैंड : यहां एनडीपीपी-भाजपा गठबंधन ने सरकार बनाई। नगालैंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की। नगा पीपुल्स फ्रंट को 27 सीटें मिलीं। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने 16 सीटें प्राप्त की। वहीं, नेशनल पीपुल्सी पार्टी को 2, जनता दल (यूनाइटेड) एवं निर्दलीय को 1-1 सीट मिली। ■

पूर्वोत्तर विधानसभाओं के चुनाव परिणाम एक नए युग की शुरुआतः नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 3 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में उत्तर-पूर्व के तीन राज्यों त्रिपुरा, नगालैंड और मेघालय में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की ऐतिहासिक विजय के अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह को भाजपा की विकास यात्रा का शिल्पी बताते हुए इस अभूतपूर्व जीत के लिए तीनों राज्यों की जनता, पार्टी कार्यकर्ताओं व पार्टी पदाधिकारियों को उन्होंने हार्दिक बधाई दी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए तीनों राज्यों (त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड) की जनता को लोकतंत्र की जीत की बधाई दी और कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की विकास नीति पर जनता की मुहर है। सभा में भारतीय जनता पार्टी की संसदीय समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन को अजान के लिए दो मिनट तक स्थगित कर दिया। इसके पश्चात् उन्होंने केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में वामपंथ की हिंसा की राजनीति के कारण शहीद हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए अपनी शहादत दी है और उनकी शहादत कभी बेकार नहीं जाने दी जायेगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विचारधारा के कारण हमारे निर्दोष कार्यकर्ताओं को मौत

देश के राजनीतिक विश्लेषकों को यह विचार करना होगा कि लोकतंत्र में सही बात से और विकास की राजनीति करके चुनाव और लोगों के दिलों को जीता जा सकता है, हिंसा, जातिवाद और नफरत की राजनीति करके नहीं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे चरितार्थ करके दिखाया है। हमने देश में पॉलिटिक्स ऑफ़ परफॉरमेंस की राजनीति की शुरुआत की है और देश की जनता ने इसमें अपना सम्पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है।

के घाट उतारा गया है, क्योंकि हमारे विरोधियों में लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने की ताकत नहीं है। उन्होंने कहा कि भय और भ्रम इन दो हथियारों से, खासकर लेफ्ट पार्टियों ने पार्टी कार्यकर्ताओं पर जो जुल्म किया, वह अकथनीय है। लेकिन यह देश के लोकतंत्र की ताकत है कि गरीब से गरीब जनता ने भी इस चोट का जवाब वोट से दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जय और पराजय स्वाभाविक है, लेकिन पार्टियों को पराजय को पचाना चाहिए लेकिन जो लोकतंत्र के बारे में बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, वही लेफ्ट पार्टियां इसे पचा नहीं पा रही हैं।

श्री मोदी ने कहा कि त्रिपुरा की जीत कोई साधारण जीत नहीं है, बल्कि यह शून्य से शिखर तक की यात्रा है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के इन तीन विधानसभाओं के चुनाव परिणाम देश में एक नए युग की शुरुआत के लिए जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का समर्थन किया है और हम पूर्वोत्तर की जनता के लिए काम करने और उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के दुष्प्रचार के बीच भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई देश के जन-सामान्य तक पहुंची है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के राजनीतिक विश्लेषकों को यह विचार करना होगा कि लोकतंत्र में सही बात से और विकास की राजनीति करके चुनाव और लोगों के दिलों को जीता जा सकता है, हिंसा, जातिवाद और नफरत की राजनीति करके नहीं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे चरितार्थ करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि हमने देश में पॉलिटिक्स ऑफ़ परफॉरमेंस की राजनीति की शुरुआत की है और देश की जनता ने इसमें अपना सम्पूर्ण विश्वास

व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जब 2014 में मैं प्रधानमंत्री बना तो दिल्ली में नार्थ-ईस्ट के युवाओं पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए हमने एक मुहिम शुरू की और नार्थ-ईस्ट के युवाओं के अंदर यह भरोसा जगाने में सफल हुए कि दिल्ली में उनके लिए सोचने वाली सरकार है। अब उनके लिए दिल्ली दूर नहीं है बल्कि हमने सरकार को उनके दरवाजे तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि हमारे डोनर मंत्रालय का पूरा सेक्रेटरिएट पूर्वोत्तर के हर राज्य में जाता है, केन्द्र सरकार के कोई-न-कोई मंत्री हर 15 दिन में नार्थ-ईस्ट के किसी-न-किसी राज्य में एक दिन बिताते हैं और वहां के विकास कार्यों को गति देते हैं। उन्होंने कहा कि हमने पूर्वोत्तर की जनता के अंदर उपेक्षा के भाव को खत्म किया।

श्री मोदी ने कहा कि देश में एक दल ऐसा भी है जहां लोग पद में बढ़ते जाते हैं पर कद में घटते जाते हैं। आज कांग्रेस का कद सबसे छोटा हो गया है। उन्होंने कहा कि जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य का रंग लाल होता है, लेकिन सूर्योदय के वक्त सूर्य का रंग केसरिया होता है। उन्होंने कहा कि देश की विधान सभाओं का आंकड़ा देखा जाए तो त्रिपुरा में बीजेपी के चुने हुए विधायक सबसे छोटी उम्र के हैं और इन युवा कैंडिडेट्स पर जनता ने भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के विकास के लिए कृतसंकल्पित है और हम जनता की आशाओं व आकांक्षाओं को पूरा करके रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह संगठन की शक्ति और कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम की जीत है। उन्होंने कहा कि मैं त्रिपुरा, नगालैंड और मेघालय में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की ऐतिहासिक जीत के लिए मैं पूर्वोत्तर की जनता का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पार्टी पदाधिकारियों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने इससे पहले सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नार्थ-ईस्ट की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'सबका साथ, सबका विकास' की नीति में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में भाजपा की जीत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की गरीब-कल्याण की नीतियों की ही जीत है। उन्होंने इस अभूतपूर्व जीत के लिए तीनों राज्यों त्रिपुरा, नगालैंड और मेघालय की जनता का हार्दिक अभिनंदन किया और कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है। ■

मोदी सरकार की उत्तर-पूर्व की विकास की नीति पर मुहर: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 3 मार्च को भाजपा के केन्द्रीय कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और उत्तर-पूर्व के तीन राज्यों त्रिपुरा, नगालैंड और मेघालय में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की भव्य एवं ऐतिहासिक जीत के लिए तीनों राज्यों की जनता का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त किया। उन्होंने अभूतपूर्व जीत के इस मौके पर त्रिपुरा में कम्युनिस्ट हिंसा में शहीद हुए पार्टी के 9 कार्यकर्ताओं को हृदय की गहराइयों से नमन करते हुए उत्तर-पूर्व के तीनों राज्यों त्रिपुरा, नगालैंड और मेघालय के प्रदेश अध्यक्षों श्री बिप्लब देब, श्री विसासोली लहोनगु, श्री शिबुन लिंगदोह और श्री राम माधव, श्री सुनील देवधर, श्री हेमंत बिस्वसर्मा, श्री नलिन कोहली, श्री किरिन रिजीजू और श्री अलफोंस को उनके अथक प्रयासों के लिए बधाई दी।

श्री शाह ने कहा कि उत्तर-पूर्व में भाजपा की यह जीत पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कई मायनों में काफी हर्ष का विषय है। उन्होंने उत्तर-पूर्व के तीनों राज्यों की जनता को हृदय से बधाई देते हुए कहा कि उत्तर-पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत से यह स्पष्ट है कि नार्थ-ईस्ट की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है और मोदी सरकार की उत्तर-पूर्व की विकास की नीति पर मुहर लगाई है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, "2014 के लोक सभा चुनावों के दौरान श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने देश की जनता से कहा था कि भारत के सर्वांगीण विकास के लिए देश के पश्चिमी हिस्से की तरह ही उत्तर-पूर्वी भाग का भी विकास होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि यदि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उत्तर-पूर्वी हिस्से का विकास सरकार की मुख्य प्राथमिकता होगी।" भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने उत्तर-पूर्व के विकास के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एक्टिव किया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई भाई के बाद शिलांग में नार्थ-ईस्ट कौंसिल की रेगुलर मीटिंग का श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को जाता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में हर 15 दिन में केंद्र सरकार के कोई-न-कोई मंत्री उत्तर-पूर्व के किसी-न-किसी राज्य में विकास कार्यक्रमों को लेकर दौरा करते हैं और विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि नार्थ-ईस्ट के विकास के लिए पैसा तो पहले भी आवंटित हुआ करता था, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और मोदी सरकार की सफल नीति के कारण पैसा विकास में परिवर्तित होने लगा और उत्तर-पूर्व के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने में हमें सफलता मिली। उन्होंने कहा कि उत्तर-पूर्व में भाजपा की यह

ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की नीतियों की ही जीत है।

श्री शाह ने कहा कि यदि त्रिपुरा, नगालैंड और मेघालय की बात करें तो त्रिपुरा में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को केवल 1.3% वोट शेयर मिला था, पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। यहां तक कि केवल एक सीट पर ही हमारी जमानत बची थी, लेकिन आज भाजपा गठबंधन को त्रिपुरा में 43 सीटों के साथ दो-तिहाई बहुमत प्राप्त हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि आज एनडीए त्रिपुरा में 50% के वोट शेयर को भी क्रॉस कर गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात, हिमाचल प्रदेश के बाद त्रिपुरा लगातार ऐसा तीसरा राज्य है, जहां भारतीय जनता पार्टी को 49 से 50% वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने वामपंथी हिंसा का डट कर सामना किया, हमारे कई कार्यकर्ता शहीद हुए, लेकिन बिना डिगे हुए, बिना झुके हुए कार्यकर्ताओं ने हर बूथ पर पार्टी की मजबूती के लिए अथक परिश्रम किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में "चलो पलटाई" का नारा दिया था और आज त्रिपुरा की जनता ने इसे आत्मसात करते हुए आज भाजपा को दो-तिहाई बहुमत के साथ भव्य जनादेश दिया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को भले ही अकेले दम पर त्रिपुरा में पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन हम अपनी परंपरा के अनुसार अपने सहयोगी के साथ सरकार चलाएंगे।

नगालैंड के चुनाव परिणाम की चर्चा करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नगालैंड में पिछली बार भाजपा को 2% से भी कम वोट मिले थे और केवल एक सीट पर जीत मिली थी जबकि अभी तक के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भाजपा को 11 सीटें मिल रही हैं। एनडीए को प्रदेश में लगभग 40% वोट मिले हैं और भाजपा गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है।

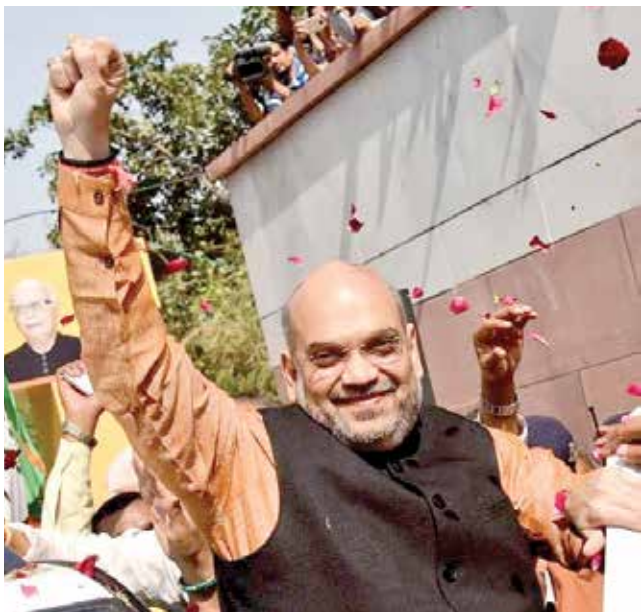

मेघालय के चुनाव परिणाम पर बोलते हुए श्री शाह ने कहा कि मेघालय में भी कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ परिवर्तन का जनादेश दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को अच्छी सफलता मिली है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर-पूर्व के तीनों राज्यों के चुनाव नतीजे आने वाले कर्नाटक विधान सभा चुनाव और लोक सभा चुनाव परिणाम के द्योतक हैं। उन्होंने कहा कि एक ज़माना था जब भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदी भाषी क्षेत्र की पार्टी मानी जाती थी, जबकि आज लद्दाख, केरल, कोहिमा से लेकर कच्छ और जम्मू-कश्मीर तक भाजपा की प्रभावी उपस्थिति है और कई गैर-हिंदी भाषी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी का अखिल भारतीय स्वरूप दुनिया के सामने है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत का सबसे ज्यादा आनंद पश्चिम बंगाल और केरल के कार्यकर्ताओं को हो रहा है, क्योंकि उन्होंने वर्षों तक वाम दलों की हिंसा की राजनीति को झेला है, हमारे कई कार्यकर्ताओं ने अपनी आहुति दी है।

श्री शाह ने कहा कि तीनों राज्यों त्रिपुरा, नगालैंड और मेघालय की जनता ने कांग्रेस को नकारा है। यहां तक कि त्रिपुरा और नगालैंड में तो कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया, कई सीटों पर तो कांग्रेस की जमानत भी जब्त हो चुकी है। यह दर्शाता है कि देश की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रही है। उन्होंने कहा कि जहां तक लेफ्ट का सवाल है तो लेफ्ट भारत के किसी भी हिस्से के लिए राइट नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले पश्चिम बंगाल और अब त्रिपुरा से वामपंथी पार्टियों की विदाई से यह स्पष्ट हो गया है कि देश में वामदलों की प्रासंगिकता अब खत्म हो चुकी है, इनको देश की जनता पसन्द नहीं करती और दोनों राज्यों से वामदलों की विदाई भारतीय जनता पार्टी के उदय की निशानी है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गांव, गरीब, किसान, दलित और आदिवासियों के लिए काम किया है, उसी का नतीजा है कि तीनों ट्राइबल बहुल राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को ऐतिहासिक सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा की 20 ट्राइबल सीटों पर 20 की 20 सीटें भाजपा गठबंधन ने जीती है। यह भारतीय जनता पार्टी, नार्थ-ईस्ट और देश के लिए एक शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के पूर्वोत्तर में शांति स्थापित करने के प्रयासों पर जनता की मुहर ने यह सिद्ध कर दिया है कि नार्थ-ईस्ट की जनता विकास और शांति चाहती है और वह संघर्ष एवं बदले की राजनीति से बाहर आना चाहती है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में पार्टी की लोकप्रियता का सबसे बड़ा पैमाना जनादेश होता है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अगुआई में देश में हुए लगभग हर चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। त्रिपुरा, नगालैंड और मेगालय में पार्टी की जीत इसी जीत की अगली कड़ी है। ■

त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देब ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ

भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री बिप्लब कुमार देब ने 9 मार्च को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गौरतलब है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा के 25 साल के शासन का अंत कर पहली बार भाजपा त्रिपुरा की सत्ता पर आसीन हुई।

राज्यपाल श्री तथागत रॉय ने अगरतला के असम राइफल्स ग्राउंड में आयोजित एक समारोह में श्री देब को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह भी इस समारोह में उपस्थित रहे।

अगरतला में जगह-जगह श्री नरेन्द्र मोदी और श्री अमित शाह की तस्वीरों वाले बड़े-बड़े पोस्टर लगाए गए थे। हवाई अड्डे से लेकर शपथ ग्रहण समारोह स्थल तक सड़क की दोनों तरफ भाजपा के झंडे लगे हुए थे। पार्टी के कार्यकर्ता भगवा परिधान पहने सड़कों पर नजर आ रहे थे।

भाजपा नेता श्री जिश्नु देव बर्मन को उप-मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। श्री जिश्नु अभी विधायक नहीं चुने गए हैं, क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र चरिलाम (अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित) में माकपा उम्मीदवार के निधन की वजह से मतदान टल गया था। इस सीट पर चुनाव 12 मार्च को कराया जाएगा।

भाजपा के पांच और उसकी गठबंधन सहयोगी इंडीजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) के अध्यक्ष श्री एनसी देवबर्मन सहित दो सदस्यों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। सर्वश्री रतन लाल नाथ, सुदीप रॉय बर्मन, प्रणजीत सिंघा रॉय, मनोज कांति देव और श्रीमती सांतना चकमा भाजपा से हैं जबकि श्री एनसी देवबर्मन और श्री मेवार कुमार जमातिया आईपीएफटी से हैं। देवबर्मन आईपीएफटी के अध्यक्ष और जमातिया महासचिव हैं।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के पास अवसर और क्षमता है जिनका प्रदेश के विकास के लिए इस्तेमाल करना होगा।

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत स्थानीय भाषा में की। उन्होंने कहा कि आज त्रिपुरा में फिर से एक बार दीपावली आई है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो इतिहास में दर्ज हो जाते हैं, त्रिपुरा का चुनाव उन्हीं में से एक है जिसकी चर्चा भविष्य में भी होती रहेगी। त्रिपुरा के नागरिकों ने ये इतिहास रचा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं त्रिपुरा के लोगों से अपील करता हूं कि आइए, हम राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं ताकि हम लोगों की ज़िंदगी बदल सकें। मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि विकास के रास्ते पर त्रिपुरा को केंद्र सरकार का पूर्ण समर्थन और सहयोग रहेगा तथा यह सहयोग सहकारी संघवाद पर आधारित होगा।

उन्होंने कहा कि सरकार का मूल मंत्र विकास, सुशासन, लोगों की भागीदारी और सबका साथ सबका विकास होगा।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि मैंने बतौर प्रधानमंत्री कई बार पूर्वोत्तर का दौरा किया है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारत पूर्वोत्तर के साथ है, भारत पूर्वोत्तर के मसलों को समझता है और हर भारतीय पूर्वोत्तर के लोगों के साथ खड़ा है।

प्रधानमंत्री बोले कि त्रिपुरा में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ है। त्रिपुरा के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिन्होंने हमें वोट दिए हैं और जिन्होंने वोट नहीं दिए हैं, ये सरकार सभी के लिए है। त्रिपुरा का हर नागरिक हमारा है, उसका विकास करना हमारा दायित्व है।

Tripura
Result Status

Status Known For 59 out of 60 Constituencies

Party	Won	Total
Bharatiya Janata Party	35	35
Communist Party of India (Marxist)	16	16
Indigenousn People's Front Of Tripura	8	8
Total	59	59

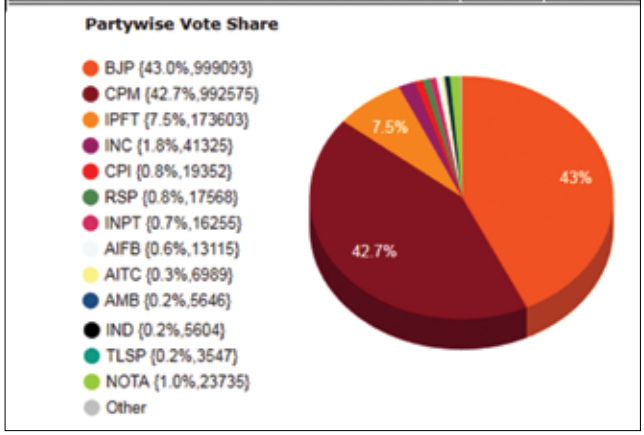

जीवन परिचय

श्री बिप्लब कुमार देब का जन्म 25 नवंबर, 1969 को त्रिपुरा के गोमती जिले के राजधर नगर गांव में हुआ। उन्होंने त्रिपुरा के उदयपुर कॉलेज से 1999 में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। वे राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। भाजपा से भी वे लंबे समय से जुड़े हैं। 2015 में उन्हें प्रदेश महासंपर्क अभियान का संयोजक बनाया गया। 2016 में उन्होंने त्रिपुरा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद का दायित्व संभाला। उनकी छवि साफ और ईमानदार नेता की है।

उन्होंने कहा कि मैं पूर्व में आए किसी भी प्रधानमंत्री से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में आया हूं। भारत के हर नागरिक को लगना चाहिए कि वह भारत माता की जय बोलता है तो उसे गर्व होना चाहिए।

शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी और डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने भी भाग लिया।

त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री माणिक सरकार ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

भाजपा राष्ट्रीय महासचिव श्री राम माधव ने बताया कि इस विशाल कार्यक्रम के लिए 100 फुट लंबा मंच बनवाया गया। हमारे लिए यह बड़ा दिन है, क्योंकि यह राज्य में राजनीतिक बदलाव की शुरुआत है। मोदीजी के विकास कार्यों से यह जीत संभव हुई है और उससे हमारे कार्यकर्ता त्रिपुरा में बदलाव की ख़ातिर काम करने के लिए प्रेरित हुए।

त्रिपुरा की 60 सदस्यों वाली विधानसभा में भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन को दो-तिहाई बहुमत हासिल हुआ है। जिन 59 सीटों पर मतदान हुए उनमें भाजपा को 35 जबकि आईपीएफटी को आठ सीटें मिली।

48 साल के श्री बिप्लब कुमार देब ने 6 मार्च को राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा प्रस्तुति किया था। राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया।

भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, गुजरात के श्री विजय रूपानी, मध्य प्रदेश के श्री शिवराज सिंह चौहान, असम के श्री सर्बानंद सोनोवाल, झारखंड के श्री रघुबर दास तथा अनेक वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। ■

नेफ्यू रियो ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

नगालैंड में 8 मार्च को भाजपा गठबंधन की सरकार बनी। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) के श्री नेफ्यू रियो ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बता दें कि नॉर्थन अंगामी-II सीट से रियो निर्विरोध चुने गए थे।

नगालैंड के राज्यपाल श्री पीबी आचार्य ने एनडीपीपी के वरिष्ठ नेता श्री नेफ्यू रियो को प्रदेश के मुख्य मंत्री पद की शपथ दिलाई। यह शपथ ग्रहण समारोह कोहिमा लोकल ग्राउंड में आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम नेफ्यू रियो के साथ 10 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्री य अध्यक्ष श्री अमित शाह, रक्षामंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे।

इससे पहले केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री अरुण सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री विसासोली लहोनगु के साथ राज्यपाल से मिलकर श्री रियो का समर्थन करने वाला एक पत्र दिया था, जिस पर भाजपा के 12 विधायकों के हस्ताक्षर थे। भाजपा नेताओं ने राज्यपाल को सूचित किया कि वाई पट्टन को विधानसभा में भाजपा के विधायक दल का नेता चुना गया है।

नेशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) के प्रदेश अध्यक्ष श्री एटो येथोमी ने कहा कि उन्होंने रियो को समर्थन देने वाला एक पत्र राज्यपाल को सौंपा है। हाल में खत्म हुए विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ एनपीएफ ने 26 सीटें जीती हैं। एनडीपीपी- भाजपा के गठबंधन ने 30 सीटें अपनी झोली में डाली हैं और उन्हें एनपीपी के दो विधायकों तथा एक जदयू और एक निर्दलीय का समर्थन हासिल है।

Nagaland
Result Status

Status Known For 59 out of 60 Constituencies

Party	Won	Total
Bharatiya Janata Party	12	12
Naga Peoples Front	27	27
Janata Dal (United)	1	1
National People's Party	2	2
Nationalist Democratic Progressive Party	16	16
Independent	1	1
Total	**59**	**59**

Partywise Vote Share

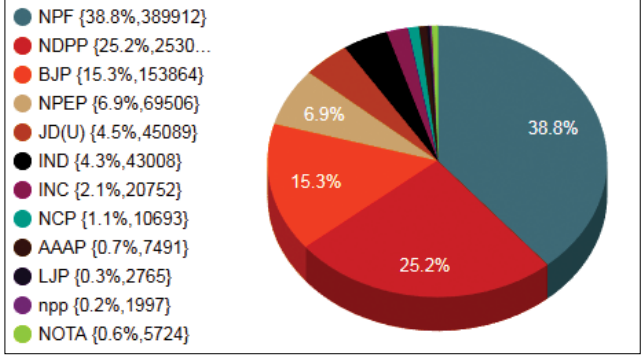

शपथ-ग्रहण समारोह का स्थल इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि एक दिसंबर, 1963 को यहीं से तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने नगालैंड राज्य के गठन की घोषणा की थी। ■

कोनराड संगमा ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ

Meghalaya
Result Status

Status Known For 59 out of 60 Constituencies

Party	Won	Total
Bharatiya Janata Party	2	2
Indian National Congress	21	21
Nationalist Congress Party	1	1
Hill State People's Democratic Party	2	2
National People's Party	19	19
United Democratic Party	6	6
Khun Hynniewtrep National Awakening Movement	1	1
People's Democratic Front	4	4
Independent	3	3
Total	**59**	**59**

Partywise Vote Share

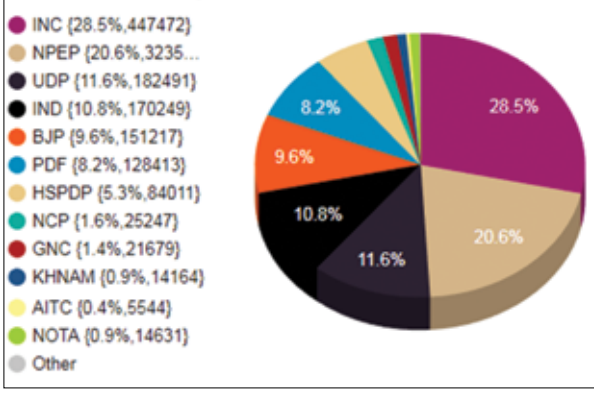

नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के अध्यक्ष श्री कोनराड संगमा ने 6 मार्च को मेघालय के मुख्य मंत्री पद की शपथ ली। मेघालय के राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद ने श्री कोनराड संगमा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। बता दें कि एनपीपी केंद्र और मणिपुर में भाजपा की सहयोगी पार्टी है।

श्री गंगा प्रसाद ने कोनराड को 5 मार्च को प्रदेश में सरकार बनाने का आमंत्रण दिया था। राज्य में पांच दलों और एक निर्दलीय के समर्थन से राजग सरकार बनी है। श्री कोनराड के साथ श्री जेम्स पीके संगमा, श्री ए. एल. हेक समेत 11 मंत्रियों ने भी शपथ ली।

श्री कोनराड संगमा के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उन्हें बधाई दी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले लोगों को यह लगता था कि नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों में सिर्फ कांग्रेस ही राज कर सकती है, लेकिन भाजपा ने बदलाव कर इतिहास रचा है।

चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद विधानसभा की स्थिति देखी जाए तो 60 में से 21 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। वहीं एनपीपी ने 19 और भाजपा ने 2 सीटों पर सफलता प्राप्त की, जबकि यूनाईटेड डेमोक्रेटिक पार्टी को 6 और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को 2 सीटें मिली हैं।

उल्लेखनीय है कि श्री कोनराड संगमा ने 5 मार्च को राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद से भेंट की थी और 60 सदस्यीय विधानसभा में 34 विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया था। बैठक के बाद श्री संगमा ने कहा, 'हमने राज्यपाल से मुलाकात की और 34 विधायकों के समर्थन का पत्र पेश किया, जिसमें 19 विधायक एनपीपी के, 6 यूनाईटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, 4 पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, 2 हिल स्टेट डेमोक्रेटिक पार्टी (एचएसपीडीपी), 2 भाजपा के और एक निर्दलीय विधायक है।' ■

तीसरी तिमाही (अक्तूबर से दिसंबर तक) में जीडीपी की वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 की तीसरी तिमाही में स्थिर (2011-12) मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 32.50 लाख करोड़ रुपये है, जो वित्त वर्ष 2016-17 की तीसरी तिमाही में 30.32 लाख करोड़ रुपये था। यह 7.2 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर दर्शाता है। स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही और दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दरें क्रमशः 5.7 तथा 6.5 प्रतिशत रहीं।

गौरतलब है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 28 फरवरी को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए स्थिर मूल्यों (2011-12) और वर्तमान मूल्यों दोनों पर ही राष्ट्रीय आय के दूसरे अग्रिम अनुमान जारी किए। साथ ही, स्थिर मूल्यों (2011-12) और वर्तमान मूल्यों दोनों पर ही 2017-18 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के तिमाही अनुमान भी जारी किए गए।

स्थिर मूल्यों (2011-12) और वर्तमान मूल्यों पर वर्ष 2017-18 के लिए जीडीपी वृद्धि दर और वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही की जीडीपी वृद्धि दरों का उल्लेख निम्न है:-

जीडीपी वृद्धि दर (प्रतिशत में)		
	स्थिर मूल्य (2011-12)	वर्तमान मूल्य
वार्षिक 2017-18 (द्वितीय अनुमान)	6.6	9.8
पहली तिमाही 2017-18(अप्रैल-जून)	5.7	9.2
दूसरी तिमाही 2017-18(जुलाई-सितंबर)	6.5	10.0
तीसरी तिमाही 2017-18(अक्टूबर-दिसंबर)	7.2	11.9

स्थिर मूल्यों (2011-12) पर सकल घरेलू उत्पाद

वित्त वर्ष 2017-18 में स्थिर मूल्यों (2011-12) पर वास्तविक जीडीपी अथवा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) बढ़कर 130.04 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच जाने का अनुमान है, जो वर्ष 2016-17 के लिए जीडीपी के प्रथम संशोधित अनुमान में 121.96 लाख करोड़ रुपये आंका गया था, वर्ष 2017-18 में जीडीपी वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वर्ष 2016-17 में जीडीपी वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रहीं थी।

स्थिर मूल्यों (2011-12) पर सकल मूल्य वर्धित (जीवीए)

स्थिर मूल्यों (2011-12) पर जीवीए वर्ष 2016-17 के 112.48 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 119.64 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच जाने का अनुमान है। वर्ष 2017-18 में बुनियादी मूल्यों पर वास्तविक जीवीए की अनुमानित वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि यह वर्ष 2016-17 में 7.1 प्रतिशत आंकी गई थी।

जिन क्षेत्रों (सेक्टर) द्वारा 7 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि दर दर्ज किए जाने का अनुमान हैं, उनमें 'लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं', 'व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण संबंधी सेवाएं, 'बिजली, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगिता सेवाएं' और 'वित्तीय, अचल संपत्ति एवं प्रोफेशनल सेवाएं' शामिल हैं। 'कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन', 'खनन एवं उत्खनन', 'विनिर्माण' और 'निर्माण' क्षेत्रों की वृद्धि दर क्रमशः 3.0, 3.0, 5.1 तथा 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

स्थिर मूल्यों (2011-12) पर प्रति व्यक्ति आय

वर्ष 2017-18 के दौरान स्थिर मूल्यों (2011-12) पर प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 86,689 रुपये हो जाने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2016-17 में यह 82,229 रुपये थी।

वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद

वर्ष 2017-18 में वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी बढ़कर 167.52 लाख करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है, जो वर्ष 2016-17 में 152.54 लाख करोड़ रुपये थी। इस तरह यह 9.8 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर दर्शाती है।

वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय आय

वर्ष 2017-18 के दौरान वर्तमान मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) 148.40 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2016-17 में 134.93 लाख करोड़ रुपये थी। यह 11.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय

वर्ष 2017-18 के दौरान प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,12,764 रुपये के स्तर पर पहुंच जाने का अनुमान है, जो वर्ष 2016-17 में 1,03,870 रुपये थी। यह 8.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। ■

जनवरी, 2018 में आठ कोर उद्योगों की वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत

आठ कोर उद्योगों का संयुक्त सूचकांक जनवरी, 2018 में 133.1 अंक रहा, जो जनवरी, 2017 में दर्ज किए गए सूचकांक के मुकाबले 6.7 प्रतिशत ज्यादा है। वहीं, वर्ष 2017-18 की अप्रैल-जनवरी अवधि के दौरान आठ कोर उद्योगों की संचयी उत्पादन वृद्धि दर 4.3 प्रतिशत रही। गौरतलब है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में शामिल वस्तुओं के भारांक (वेटेज) का 40.27 प्रतिशत हिस्सा आठ कोर उद्योगों में शामिल होता है।

सीमेंट: जनवरी, 2018 के दौरान सीमेंट उत्पादन (भारांकः 5.37%) जनवरी, 2017 के मुकाबले 20.7 प्रतिशत ज्यादा रहा। अप्रैल-जनवरी, 2017-18 के दौरान सीमेंट उत्पादन बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.4 प्रतिशत अधिक रहा।

बिजली: जनवरी, 2018 के दौरान बिजली उत्पादन (भारांकः 19.85%) में जनवरी, 2017 के मुकाबले 8.2 प्रतिशत का इजाफा हुआ। अप्रैल-जनवरी, 2017-18 में बिजली उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 5.4 प्रतिशत अधिक रहा।

कोयला: जनवरी, 2018 में कोयला उत्पादन (भारांकः 10.33%) जनवरी, 2017 के मुकाबले 3.0 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल-जनवरी, 2017-18 में कोयला उत्पादन की वृद्धि दर पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 1.5 प्रतिशत अधिक रही।

रिफाइनरी उत्पाद: पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन (भारांकः 28.04%) जनवरी, 2018 में 11.0 प्रतिशत बढ़ गया।

अप्रैल-जनवरी, 2017-18 में पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 4.7 प्रतिशत अधिक रहा।

इस्पात: जनवरी, 2018 में इस्पात उत्पादन (भारांकः 17.92%) 3.7 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल-जनवरी, 2017-18 में इस्पात उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 6.4 प्रतिशत ज्यादा रहा।

नोट 1: नवंबर, 2017, दिसंबर, 2017 और जनवरी, 2018 के आंकड़े अंतरिम हैं।

नोट 2: अप्रैल, 2014 से ही बिजली उत्पादन के आंकड़ों में नवीकरणीय अथवा अक्षय स्रोतों से प्राप्त बिजली को भी शामिल किया जा रहा है। ■

दाल और तिलहनों की खरीद पर केंद्रीय सरकार की गारंटी दोगुनी

9,500 करोड़ रुपये की मंजूरी

कैबिनेट ने 28 फरवरी को एनएएफईडी द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाल और तिलहनों की खरीद के लिए 9,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सरकार की गारंटी को दोगुना करते हुए 9,500 करोड़ रुपये को मंजूरी दी। दरअसल, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने विनियमन और सरकार की गारंटी विस्तार को मंजूरी प्रदान कर दी। यह गारंटी ऋण दाता बैंक द्वारा नेशनल एग्रीकल्चर कॉपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (एनएएफईडी) को दी जाती है।

लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ (एसएफ़एसी) को वर्तमान दायित्वों और मौजूदा दावों के निपटान को पूरा करने के लिए मूल्य सहायता योजना (पीएसएस) के तहत दालों और तिलहनों की खरीद प्रक्रिया के लिए 45 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। 1% की सरकारी गारंटी शुल्क के छूट के साथ यह सरकारी गारंटी भारत सरकार की तरफ से पांच साल की एक निश्चित अवधि 2021-22 तक के लिए प्रदान की गई है।

चूंकि लगभग सभी दालों और तिलहनों का बाजार मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के प्रावधानों के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित है, इसलिए यह गारंटी वस्तुओं के मुख्य आगमन की अवधि के दौरान बिक्री करने, उच्च निवेश व उत्पादन को प्रोत्साहित करने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के साथ लाभकारी मूल्य प्रदान करने से इन किसानों को सुरक्षा मिलेगी। साथ ही, इससे मध्यस्थता की लागत कम आएगी। ■

पीएमएवाई (शहर) के तहत शहरी गरीबों के लिए 1,28,509 किफायती घर मंजूर

केंद्र की ओर से 1,928 करोड़ रुपये की सहायता के साथ 9,364 करोड़ रुपये का निवेश मंजूर

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत शहरी गरीबों के लिए 1,28,509 अधिक किफायती घरों के निर्माण के लिए केंद्र की ओर से 1,928 करोड़ रुपये की सहायता के साथ 9,364 करोड़ रुपये का निवेश मंजूर किया है। गौरतलब है कि 27 फरवरी को केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की आयोजित 31वीं बैठक में इसका अनुमोदन दिया गया। छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पुडुचेरी (केंद्र शासित प्रदेश) राज्यों में 184 शहरों के लिए ये परियोजनाएं स्वीकृत की गईं।

हरियाणा के 33 शहरों और कस्बों में 62,451 घरों को मंजूरी दी गई। इसके लिए 948 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 6,844 करोड़ रुपये निवेश को अनुमति दी गई। उत्तर प्रदेश के 95 शहरों और कस्बों में 36,056 घरों के निर्माण के लिए 541 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 1,287 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी दी गई। साथ ही, छत्तीसगढ़ के 54 शहरों में 28,029 सस्ते घरों को 1,151 करोड़ रुपये के साथ केंद्रीय सहायता के रूप में 420 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। इसके अलावा पुडुचेरी के दो शहरों में 1,973 घरों के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 83 करोड़ रुपये के निवेश की अनुमति दी गई।

पीएमएई (शहर) के हिस्से के तहत बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन (बीएलसी) घटक के अंतर्गत 51, 9 40 नए घरों के निर्माण को

स्वीकृति मिली थी जिनमें उत्तर प्रदेश में 15,033, छत्तीसगढ़ में 10,572, हरियाणा में 2,049 और पुडुचेरी में 1,973 घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई। यानी साझेदारी में किफायती घर (एएचपी) के तहत हरियाणा को कुल 54,560 घर उत्तर प्रदेश को 4,552 घर, छत्तीसगढ़ को 17,457 घर मिले।

उपर्युक्त प्रस्तावित घरों के मुताबिक केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति ने पीएमएवाई (शहर) के तहत 39,15,402 घरों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की। इसके बाद आरएवाई योजना के तहत लाने के बाद पीएमएवाई (शहर) के अंतर्गत कुल 40,57,250 घरों के निर्माण के लिए फंड मुहैया कराने को अनुमति दी गई। ■

प्रधानमंत्री द्वारा 'प्रगति' के जरिये केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य का जायजा

पिछली प्रगति की 23 बैठकों के दौरान कुल 208 परियोजनाओं की समीक्षा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 28 फरवरी को 'प्रगति' के जरिए 24वीं वार्ता की अध्यक्षता की। यह 'प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन' (प्रगति) के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुविध मंच है। इस बैठक में 17 क्षेत्रों में लोक शिकायतों के निपटारे की भी समीक्षा की गयी। गौरतलब है कि इसके पूर्व प्रगति की 23 बैठकों के दौरान कुल 208 परियोजनाओं की समीक्षा की गयी थी।

दरअसल, 24वीं बैठक में प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। उत्तराखंड राज्य सरकार ने द्रोण इमेजरी के जरिए निर्माण कार्य की प्रगति का ब्यौरा पेश किया। प्रधानमंत्री ने दिल्ली पुलिस से संबंधित शिकायतों के निपटारे और अन्य कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने शिकायतों को दूर करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने की अहमियत पर जोर दिया। श्री मोदी ने रेलवे, सड़क, बिजली, पेट्रोलियम और कोयला क्षेत्र की 10 संरचना परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। ये परियोजनाएं विभिन्न राज्यों में चल रही हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु और केरल शामिल हैं। इन परियोजनाओं की लागत 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक है। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। ■

चिति है हमारे राष्ट्र का प्राण

| दीनदयाल उपाध्याय |

प्रत्येक व्यक्ति सुख की कामना लेकर कार्य करता है- भौतिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। सामूहिक और व्यक्तिगत रीति से विचार करते हुए चार पुरुषार्थ सामने आते हैं। इन पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। हम सभी एक-दूसरे पर निर्भर हैं। हम परस्परावलंबी हैं। व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि तथा परमेष्टि, हम इस परस्परानुकूलता तक पहुंचे। इसके लिए कर्म का सिद्धांत और यज्ञ तक की कल्पना करनी पड़ेगी। समाज का कौन सा ढांचा होना चाहिए, जिसमें ये सब चीजें प्राप्त हो जाएं। पश्चिम ने इस बाह्य रचना पर बहुत जोर दिया है। केवल रचना-मात्र से ही जो प्राप्त करना चाहते हैं, वह नहीं हो सकता।

दो चीजें होती हैं-रूप और तत्त्व। तत्त्व के बिना रूप का कोई अर्थ नहीं है, किंतु पश्चिम में रूप पर ध्यान दिया जाता है। उसके लिए संस्था प्रजातंत्र या राजतंत्र चाहिए, फिर संसदीय लोकतंत्र चाहिए। हमारे यहां बाह्य स्वरूप पर इतना ज़ोर नहीं दिया जाता। हम समाज के तत्त्व, स्वत्व और बलशाली होने पर जोर देते हैं, क्योंकि केवल रचना करने से तो काम नहीं चलेगा। चाबी के बिना घड़ी कैसे चलेगी? चाबी तो उसमें भी हाथ से भरनी पड़ती है। बिना हिले-डुले काम नहीं चल सकता। मान लो कि बिना हिले-डुले कोई ऐसा यंत्र बन जाए, जिसमें कुछ श्रम न करना पड़े समाज की भी रचना स्वयं ही चलती रहे, कुछ न करना पड़े। किसी ने कहा कि सारी व्यवस्था यदि अच्छी है तो फिर विकार क्यों आया? वास्तविकता यह है कि व्यवस्थाएं तो शक्ति के आधार पर ही चलती हैं। कुशल कारीगर को हथियार तो चाहिए ही, तभी वह अपनी कारीगरी दिखा सकता है। पेड़ काटने के लिए यदि आप कुल्हाड़ी-आरी देते हैं, तभी पेड़ कटेगा। थर्मामीटर से तो पेड़ नहीं कटता। दूसरी ओर, यदि मजबूत कुल्हाड़ी रख दिया, काटने वाले के हाथ में शक्ति ही नहीं है, तब पेड़ कैसे कटेगा? वह तो अपना पैर ही काट लेगा। किंतु दूसरी बात का भी विचार किया जाना चाहिए कि कौन चलाने वाला है। हमें जो कुछ प्राप्त करना है, उसके लिए साधन रूप में चार बातों की आवश्यकता होती है-शिक्षा, स्वतंत्रता, शांति और पौरुष। इसके लिए चार प्रकार के साधन हैं-पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहिए, मोक्ष चाहिए, अर्थ चाहिए और शिक्षा चाहिए, लेकिन शिक्षा का अर्थ केवल जानकारी ही नहीं। यह तो छोटा सा अंग है। उन सारी बातों पर विचार करना होगा, जिनसे हम अपने ध्येय की प्राप्ति कर सकते हैं। हमें पुरुषार्थ करना होगा। संस्कारों के द्वारा अध्यापन भी आवश्यक है, स्वाध्याय, चिंतन, मनन-इनके द्वारा अपने अंदर की शक्तियों को जाग्रत करते हैं। लोकमत भी इसी दिशा में हो सकता है। शिक्षा हुई तब भी स्वतंत्रता की भूख तो मानवता को सदा से रही है। मानवता के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता ही सब कुछ नहीं है, पर राज्य से छुटकारा मिलना ही स्वतंत्रता नहीं है। अपने लोगों के राज्य करते हुए भी हम यदि स्वत्व के आधार पर चलें, तभी हम स्वतंत्र हो सकते हैं। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक-हर तरह की स्वतंत्रता चाहिए।

हम किसी देश की अर्थ नीति से न बंधे रहें, यह ठीक है। किंतु कुछ और बातें भी हैं-धन के अभाव में आर्थिक परतंत्रता हो जाती है। रोटी, शरीर की निपुणता के लिए जो-जो भौतिक सामर्थ्य चाहिए, साधन सामग्री उपलब्ध करने के लिए धन का अभाव नहीं रहना चाहिए। धन के अभाव में रोटी कमाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ब्राह्मण अपना धर्म-कर्म छोड़कर दूसरों के आगे हाथ फैलाए, तो ठीक नहीं लगता, लेकिन धन मिल जाने पर भी आर्थिक परतंत्रता नहीं गई। इसका कारण है, धन के प्रति आसक्ति, कंजूस होना। कोई व्यक्ति बहुत धनवान है, खाना नहीं खाता, पैसा जोड़कर रखता जाता है। वह साधन को साध्य मानकर चलता है। गाड़ी में से उतरकर तांगा, रिक्शा में न बैठकर पैदल ही चलने लगता है। रास्ते में प्यास लगती है तो भी पैसा ख़र्च नहीं करना चाहता। जेब से रुपया निकालकर देखा और सोचने लगा, 'सोलह कला अवतार टूट जाएगा। चाहे मर जाऊं, पर तुझे न भुनाऊंगा।' कहकर अपने पास ही रख लिया। यह भी एक प्रकार की परतंत्रता है। वह परतंत्र है स्वतंत्र नहीं। जिसे पता ही नहीं कि कैसे ख़र्च करे, निमित्त भी पता नहीं, ऐसा व्यक्ति भी आर्थिक दृष्टि से परतंत्र कहा जाएगा।

आसक्ति ही नहीं तो विलास बुद्धि भी न हो, 'मेरी कमीजें बारह चाहिए, जूते आठ', हॉस्टल के कमरे में जूतों का बाज़ार सा खुला था। भोग विलास की वृत्ति भी स्वतंत्र न होने देगी। तीसरी बात यदि यह पता ही नहीं कि इसे ख़र्च कैसे करें, निमित्त भी पता नहीं, ऐसा व्यक्ति भी परतंत्र कहलाता है। हजरत मूसा (यहूदियों के पैगंबर) पृथ्वी पर जब आए तो उन्होंने एक स्त्री को देखा। कुछ तन ढकने को नहीं था। उसने हजरत मूसा से कहा कि भगवान् से कहो कि कुछ ढकने को तो दे। इसी तरह एक अमीर आदमी मिला। उसने कहा कि भगवान् से पूछो कि इस धन को कैसे ख़र्च करूं। तो ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करता। आलस्य, तामसिक भावना, भोग-विलास, अभाव और अंत में वही परतंत्रता। इसीलिए लोग आर्थिक दृष्टि से परतंत्र हो जाते हैं। राजा हर्ष' अपने काल में पांच वर्ष तक कमाकर सब कुछ दान कर देता था। रघु ने भी सब बांट दिया। मिट्टी का बरतन ही बचाया। फिर कुबेर पर आक्रमण कर गुरु दक्षिणा दी। अतिरिक्त धन को अच्छे काम में लगाना चाहिए।

जहां लड़ाई, वहीं पर शांति; हमारे यहां नहीं मानी गई। मन की शांति, समाज की शांति, सभी प्रकार की शांति मिलनी चाहिए-भौतिक,

मानसिक, बौद्धिक। मृत्यु की शांति नहीं है, जहां सृष्टि की रचना हो और सभी व्यवस्था ठीक हो, ऐसी शांति चाहिए। भगवान् कृष्ण ने महाभारत का युद्ध भी शांति के लिए कराया। शांति आंतरिक तथा बाह्य जीवन की भी होनी चाहिए। साथ-साथ पौरुष भी तो चाहिए। इसमें पराक्रम, प्रयत्न, निष्ठा, विवेक होना चाहिए, दुस्साहस पौरुष के अंतर्गत नहीं आता। जहां पर साधन होते हैं, वहीं पर व्यवस्था का प्रश्न आता है।

इन साधनों के साथ-साथ फिर हमारे चार आश्रम, चार वर्ण होते हैं। व्यक्ति की आश्रम की दृष्टि से व्यवस्था की जाती है। इन्हीं के द्वारा समाज के प्रति व्यक्ति को कर्तव्य का पालन करना चाहिए, तभी परस्परानुकूलता आती है। वर्ण व्यवस्था में हरेक का विशिष्ट कार्य होता है। आजकल एक नारा है वर्ग विहीन समाज, जो ग़लत है। यह वहीं हो सकता है, जहां अराजकता का वातावरण हो। शिक्षार्थी और शिक्षक, परोसने वाले और भोजन करने वाले एक ही वर्ग नहीं है। वर्गों का विभाजन कार्यानुसार होता है। मार्स ने केवल पैसे के आधार पर विभाजन किया। हमने ग़रीब-अमीर नहीं तो, कर्तव्य के आधार पर वर्गीकरण किया। समाज में ज्ञान, शिक्षण, रक्षा, अर्थ, सब कुछ प्राप्त हो सके, इसकी व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। जिन साधनों के आधार पर सब बढ़ सकते हैं, वैसे लोग चाहिए। आप लोग तो रेलगाड़ी में आराम से बैठकर चले जाते हैं, लेकिन इंजन में किसी न किसी को काम करना पड़ता है। आप लोग तो आराम से रात को गाड़ी में सोते हुए जाते हैं, लेकिन कितने ही लोग जागते हैं रात भर स्टेशन और गाड़ी में। तब व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। एक-दूसरे के साथ वैज्ञानिक आधार पर, परस्परानुकूलता के आधार पर व्यवस्था करनी पड़ती है। कार्य के आधार पर व्यवस्था करनी पड़ती है। ये ही चार मोटे कार्य दुनिया के सभी देशों में किसी-न-किसी रूप में रहते हैं। इन चार संस्थाओं का हमारे यहां सूक्ष्म विवेचन किया गया है। समाज शास्त्र इन्हें पांच संस्थाओं में बांटता हैं-1. परिवार, 2. शिक्षा, 3. धर्म, 4. वाणिज्य, और 5. राज्य या राजनीतिक संस्थान। आज राज्य की संस्था को छोड़कर बाक़ी कोई बहुत संगठित नहीं है।

पश्चिम ने राज्य के हाथ में ही सब कुछ दे दिया। बाक़ी संगठन राज्य पर क़ब्ज़ा करना चाहते हैं। पोप और ख़लीफ़ाओं ने राज्य को क़ाबू में कर लिया या राज्य ने बाक़ी पर क़ब्ज़ा कर लिया। इंग्लैंड के चर्च ने राज्य पर क़ब्ज़ा किया। रूस ने श्रमिकों के द्वारा राज्य पर क़ब्ज़ा किया। इसका कारण था, वहां केवल राज्य संस्था थी। हमने कहा, सब संगठित हों तो चारों में कोई विरोध नहीं होगा। व्यवस्था का अर्थ संगठित जीवन होता है। हमारे यहां तभी वर्ण व्यवस्था पर जोर दिया जाता है। जहां यह व्यवस्था नहीं, उसे मलेच्छ देश या राज्य कहा। ऐसी जगह रहना ठीक नहीं समझा गया। हम वर्ग बनाते हैं। अलग-अलग व्यवस्था करते हैं। वर्ग तो हुए, किंतु भेद कहां है? आपस में ऊंच-नीच का विशेष स्थान नहीं है। सब समाज के अंग हैं। विभाग तो चाहिए वर्ग चलाने के लिए। समाज की भी पांच संस्थाएं होती हैं। शक्तियों का विभक्तीकरण करना पड़ता है। समाज में यदि कहीं गड़बड़ आई तो एक वर्ग बन जाता है, जो अपना काम छोड़, बाक़ी की बातों पर विचार करना शुरू कर देता है।

जब ये वर्ग एक-दूसरे पर क़ब्ज़ा करना चाहते हैं तो वहीं गड़बड़ हो जाती है। जातियां बन जाती हैं। जैसे एक जाति कबीरपंथी बन गई। जब एक संस्था बाक़ी के बीच में दखल दे तो समस्या पैदा होती है। व्यापारी राज्य पर क़ब्ज़ा करना चाहे, राज्य शिक्षा पर, तो इस दखल (Interference) को वर्ण-संकरता कहते हैं। राज्य ने अपना काम छोड़ दिया। सरकार पुलिस, सेना, डाकू आदि का ख़याल छोड़कर भिलाई का कारख़ाना, जीवन बीमा आदि पर ध्यान देने लगती है। परिणामतः व्यवस्था बिगड़ती है। भ्रष्टाचार बढ़ता है। यह वर्ण-व्यवस्था कर्तव्य, गुणों के आधार पर चलने वाली वैज्ञानिक व्यवस्था है। यह प्रतिबंधक नहीं, जन्म से या कर्म से सुविधानुसार होता है। जितने साधन चलते हैं, वे तत्त्व के बलबूते पर। तत्त्व समाज में आत्मीयता, स्वत्व लाता है। जैसे कुटुंब के अंदर ज्ञान होता है, लेकिन जब वह ज्ञान क्षीण हो जाता है तब अव्यवस्था पैदा होती है। शरीर से आत्मा निकल जाती है तो सभी कुछ ख़त्म हो जाता है।

राष्ट्र की आत्मा यह संस्कृति है। इसके लिए एक शास्त्रीय शब्द है 'चिति'। यह चिति ही समाज की विशेषता है। इसकी रक्षा के लिए सभी प्रयत्नशील रहते हैं। बाक़ी सब कुछ छोड़कर भी इसे लेने को सब तैयार रहते हैं। चिति हमारे लिए परम सुख है। हमारे यहां धर्म की भावना, निष्ठा को 'चिति' रूप में स्वीकार किया गया है। मोक्ष को परम पुरुषार्थ इसीलिए कहा गया है। धर्म के नाम पर कितने ही लोगों को बलिदान देना पड़ा। छोटे-से-छोटे व्यक्ति ने भी बलिदान दिया। यह स्वभाव हमारे अंदर पैदा होते ही माता के दूध द्वारा आता है। यह हक़ीक़त है। गुरु गोविंद सिंहजी के बच्चे बलिदान हो गए थे, लेकिन उनके अंदर इतनी दृढता कहां से आई, इतना कोई शायद करोड़ प्रशंसा कमाकर भी न कर पाए। हमारा मस्तक गौरव से ऊंचा हो जाता है, बलिदानी लोगों की कथा जब हम सुनते हैं। यदि रोटी ही सबकुछ होती तो लोग आज धर्म के नाम पर घर आदि क्यों छोड़ देते हैं। आर्थिक समस्या ही सबकुछ होती तो ऐसा नहीं होता। उनके अंतर में भी चिति का भाव छुपा हुआ होता है। क्या ईरान में सब मुसलमान बन गए? कुछ पारसी अपवादस्वरूप जैसे हमारे

यहां अपवादस्वरूप मुसलमान बने। राष्ट्र जीवन का केंद्र धर्म नहीं कहा, 'चिति' के आधार पर समाज की संगठित शक्ति होती है, जिसे विराट् कहा। इसके जाग्रत् होने पर ही फिर समाज टिकता है। फिर सब व्यवस्था ठीक चलती है। समष्टि, भूत शक्ति यह विराट् Joint Stock Company लुटेरों का नहीं, अपितु चिति एवं धर्म के आधार पर संगठन होता है। यह शरीर में प्राण की तरह रहती है, जिसके कारण इंद्रियां काम करती हैं। इंद्रियों का यदि आपस में झगड़ा हो जाए तो सबकुछ गड़बड़ा जाता है। एक बार शरीर की सब इंद्रियों में आंख, कान, हाथ, पैर में आपस में झगड़ा हो गया। सभी एक-दूसरे से अपने को बड़ा बताने लगे। उनका झगड़ा ख़त्म नहीं हो रहा था, तो सारे मिलकर ब्रह्माजी के पास गए। ब्रह्माजी ने उन्हें सुझाया कि स्वयं सारे आपस में निर्णय कर लो। जिसके न करने से सब कुछ बेकार हो जाए, वही सबसे बड़ा है। सारे ख़ुशी-ख़ुशी लौट आए। सबसे पहले आंखों ने सोचा कि हमें छुट्टी पर जाना चाहिए, तब इनको पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है। आंखें चली गईं। लेकिन शरीर ने टटोल-टटोलकर काम चला लिया। किसी ने रास्ता दिखा दिया। आंखों ने वापस आकर हालचाल पूछा। लेकिन वहां तो सबकुछ ठीकठाक है। अबकी बार कानों ने सोचा कि अब हमें छुट्टी करके देखना चाहिए। लेकिन कानों के बिना भी इशारे से काम चल गया। अब हाथों का नंबर था। हाथ चले गए। लेकिन हाथों और पैरों के बिना भी सरक-सरक कर काम चल गया। अब प्राणों की बारी आई, प्राणों ने सोचा कि सभी ने आजमाकर देख लिया है। अब मैं भी आजमाकर देख लूं। लेकिन जैसे ही प्राण जाने लगे, सभी कुछ ठंडा होने लगा। आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। हाथ-पैर सुन्न हो गए। यहां तक कि बुद्धि ने भी सोचना बंद कर दिया। सभी ने प्राणों से प्रार्थना की कि वे न जाएं। अब हमें पता चल गया है कि प्राण ही सबसे बड़े हैं।

यानी हमारी चिति हमारे राष्ट्र का प्राण है। प्राण यदि कमजोर हो जाए तो सभी इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं। प्राणों को बलवान करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ने बाह्य के रूप के स्थान पर तत्त्व का विचार किया। किसी ने कहा कि दूध अच्छा, किसी ने दूध फटा हुआ पीया था, उसने कहा कि दूध तो ख़राब होता है। जिसको जैसा अनुभव हुआ, उसने वैसी ही परिभाषा दी। एक मंडल बनाया गया जाति-पांति का भेदभाव मिटाने के लिए, लेकिन जाति-पांति तोड़क मंडल के नाम से एक अलग ही जाति बन गई। पेड़ के पत्ते सूख रहे हैं, झड़ रहे हैं। उनके झड़ने से काम नहीं चलेगा। उनकी कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो व्यवस्था लाभदायक नहीं है, चिति के अनुकूल नहीं है, वह भी अपने आप समाप्त हो जाएगी। राष्ट्र के प्राणों को जगाने का काम करना पड़ेगा। शक्ति का जागरण करना होगा। राष्ट्र की साधना का हमारा काम धर्म के आधार पर ही होता है। ■

- संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : दिल्ली (13 जून, 1958)

राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 1 मार्च को राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण (एनएफआरए) की स्थापना और एनएफआरए के लिए अध्यक्ष के एक पद, पूर्णकालिक सदस्यों के तीन पदों व एनएफआरए के लिए सचिव का एक पद के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

इस निर्णय का उद्देश्य लेखापरीक्षा के कार्य, जो कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा लाए गए परिवर्तनों में से एक है, इसके लिए एक स्वतंत्र विनियामक के रूप में एनएफआरए की स्थापना करना है। वित्त संबंधी स्थायी समिति की विशिष्ट सिफारिशों (उसकी 21वीं रिपोर्ट) में यह प्रावधान करना शामिल था।

प्रभाव: इस निर्णय से विदेशी/देश में निवेश में सुधार, आर्थिक विकास में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुरूप कारोबार के वैश्वीकरण को अनुसमर्थन तथा लेखापरीक्षा व्यवसाय के सतत विकास में सहायता मिलेगी।

न्याय क्षेत्र: अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत सनदी लेखाकारों और उनकी फर्मों की जांच करने के लिए एनएफआरए का कार्यक्षेत्र सूचीबद्ध कंपनियों तथा वृहद गैर-सूचीबद्ध कंपनियों को कार्य क्षेत्र में लाना है, जो नियमों में निर्धारित अपेक्षा के अयोग्य है। केन्द्र सरकार ऐसे अन्य निकायों की जांच के लिए भी कह सकती है, जहां सार्वजनिक हित अंतर्विष्ट हो।

चार्टर्ड अकांटेंट अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अनुसार आईसीएआई की व्याप्त विनियामक भूमिका सामान्य रूप से उनके सदस्यों तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों से संबंधित लेखापरीक्षा के संबंध में विशेष रूप से जारी रहेंगी और थ्रेशहोल्ड सीमा से नीचे सार्वजनिक गैर-सूचीबद्ध कंपनियों को नियमों में अधिसूचित किया जाएगा।

गुणवत्ता पुनरीक्षा मंडल (क्यूआरबी) की प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों, निर्धारित थ्रेडहोल्ड से कम सार्वजिनक गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में गुणवत्ता लेखापरीक्षा भी जारी रहने के साथ-साथ उन कंपनियों की लेखापरीक्षा के संबंध में भी एनएफआरए द्वारा क्यूआरबी को यह कार्य सौंपा जा सकता है।

पृष्ठभूमि: लेखापरीक्षा घोटालों के दृष्टिगत विश्व में विभिन्न कार्य क्षेत्रों में महसूस की गई जरूरत के मद्देनजर एनएफआरए की स्थापना की जरूरत नहीं है, जिसका उद्देश्य इसका विनियमन कर रहे तंत्र से इतर स्वतंत्र विनियामकों को स्थापित करना और लेखापरीक्षा मानकों को लागू करना, लेखापरीक्षा की गुणवत्ता व लेखापरीक्षा फर्मों की स्वतंत्रता को सुदृढ़ बनाना है। अतएव, कंपनियों की वित्तीय स्थिति के प्रकटीकरण में निवेशक व सार्वजनिक तंत्र का विश्वास बढ़ाना है। ■

ब्रह्मलीन हुए जगदगुरु जयेंद्र सरस्वती

(18 जुलाई 1935 – 28 फरवरी 2018)

कांची कामकोटि पीठ के प्रमुख जगदगुरु श्री जयेंद्र सरस्वती शंकराचार्य 28 फरवरी को ब्रह्मलीन हुए। उन्होंने तमिलनाडु के कांचीपुरम में अंतिम सांस ली। वह 83 साल के थे। 69वें शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती ने न केवल रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ा, बल्कि मठ की गतिविधियों का विस्तार कर समाज कल्याण, ख़ासकर दलितों की शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी किये। वे वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने मठ को एक नई दिशा दी। पहले मठ सिर्फ आध्यात्मिक कार्यों तक सीमित होता था, लेकिन श्री जयेंद्र सरस्वती ने धार्मिक संस्थानों को सामाजिक कार्यों से जोड़ा।

दरअसल, उनका आंदोलन समाज के सबसे निचले स्तर पर खड़े लोगों को मदद पहुंचाने के लिए था। पहले मठ कांचीपुरम और राज्य के भीतर तक सीमित था। वे इसे उत्तर-पूर्वी राज्यों तक ले गए। वहां उन्होंने स्कूल और अस्पताल शुरू किए।

श्री जयेंद्र सरस्वती का वास्तविक नाम सुब्रमण्यन महादेव अय्यर था और उनका जन्म 18 जुलाई 1935 को हुआ था। 68वें शंकराचार्य श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती ने सुब्रमण्यन को 22 मार्च 1954 को कांची मठ के पीठाधिपति के पद पर आसीन किया। उन्होंने ही इन्हें जयेंद्र सरस्वती का नाम दिया।

गौरतलब है कि कांची मठ तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थापित है। यह पांच पंचभूतस्थलों में से एक है यहां के मठाधीश्वर को शंकराचार्य कहते हैं। यह दक्षिण भारत के महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, 'जगदगुरु जयेंद्र सरस्वती शंकराचार्य के निधन से गहरा दुख हुआ है। वह लाखों भक्तों के लिए अनुकरणीय रहेंगे। उनकी आत्मा को ओम शांति।' अगले ट्वीट में श्री मोदी ने लिखा, 'जगतगुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती सेवा कार्यों में सबसे आगे थे। उन्होंने कई ऐसे संस्थान शुरू किए जिसके चलते गरीबों और दलितों का जीवन बदल गया।'

@narendramodi

जगदगुरु जयेंद्र सरस्वती शंकराचार्य के निधन से गहरा दु:ख हुआ है। वह लाखों भक्तों के लिए अनुकरणीय रहेंगे। उनकी आत्मा को ओम शांति। जगतगुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती सेवा कार्यों में सबसे आगे थे। उन्होंने कई ऐसे संस्थान शुरू किए, जिसके चलते गरीबों और दलितों का जीवन बदल गया।

@AmitShah

श्री जयेन्द्र सरस्वती शंकराचार्य की शिक्षा, बुद्धिमत्ता और गरीबों को शिक्षित करने के लिए किए गए कार्यों को आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। वह एक आध्यात्मिक सितारे के रूप में चमकते रहेंगे। उन्होंने समाज के हित में कई कार्य किए। उनके अनुयायियों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदना है।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने अपने शोक-संदेश में कहा कि कांची कामकोटि पीठम के शंकराचार्य परम पूज्य श्री जयेंद्र सरस्वती की महासमाधि का समाचार प्राप्त हुआ। मैं उनके आकस्मिक निधन से अत्यंत दुखी और स्तब्ध हूं। अपने उपदेशों, अपनी विद्वता, प्रज्ञता और गरीबों को शिक्षित करने एवं वंचितों के कल्याण हेतु किये गये अनुकरणीय कार्य के लिए वे हमेशा याद किये जायेंगे।

श्री शाह ने कहा कि शंकराचार्य पूज्यपाद श्री जयेंद्र सरस्वती अध्यात्म के एक जाज्वल्यमान प्रकाश स्तंभ थे, जिन्होंने समाज की भलाई एवं उनके उत्थान के लिए अतुलनीय योगदान दिया और मानव जाति की अनंत सेवा की। उनका निधन सम्पूर्ण मानव जाति के लिये एक अपूरणीय क्षति है। मानव कल्याण और आध्यात्मिकता के प्रचार-प्रसार में उनका योगदान समाज के लिये सतत प्रेरणा का काम करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि परम पूज्य शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती जी पांच पंचभूतस्थलों में से एक कांची कामकोटि मठ के 69वें शंकराचार्य थे। केवल 19 वर्ष की आयु में 1954 में वे कांची कामकोटि मठ के शंकराचार्य पद पर आसीन हुये थे।

यही नहीं, हिन्दू धर्म के प्रचार-प्रसार में अहम रोल निभाने वाले श्री जयेंद्र सरस्वती ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विभिन्न पक्षों के साथ बातचीत की। उन्होंने सहमति के जरिए राम मंदिर निर्माण के रास्ते निकालने की भी कोशिश की। ■

कृषि विकास से भारत का विकास

| डॉ. शिव शक्ति बक्सी |

किसानों, कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत पर ध्यान केंद्रित करना भारत के चौतरफा विकास के लिए नया मंत्र है। इस बात को महसूस किया जा रहा है कि अगर भारत को एक उच्च विकास पथ पर आगे बढ़ना है, तो कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाना बेहद महत्वपूर्ण है। और एक नई कृषि पर्यावरण प्रणाली बनाए बिना ऐसा करना संभव नहीं है। इस साल के बजट में जो किया गया है वह इस वक्त बहुत जरूरी था, इसमें कृषि क्षेत्र को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दिया गया है और किसानों व ग्रामीण गरीबों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा गया है। उच्च विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य, जो अब पहुंच से बाहर दिखाई नहीं देता और यह कृषि क्षेत्र के साथ-साथ लाखों-करोड़ों किसानों के जीवन को बदलने के लिए तैयार है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'न्यू इंडिया' की परिकल्पना में 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करना सबसे प्रमुख लक्ष्य है। यह बजट पिछले बजटों में उठाए गए कदमों को और अधिक मजबूत करते हुए इस दिशा में आगे बढ़ाता है और एक व्यापक व समावेशी कृषि पर्यावरण व्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ना सुनिश्चित करता है। फसलों की लगत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का निर्णय किसानों का जीवन बदलने और भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार को मजबूत करने के साथ-साथ कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन करने के लिए तैयार है। इस अभूतपूर्व घोषणा को मत्स्य पालन, पशुपालन, बांस की खेती सहित कृषि गतिविधियों से सम्बंधित अन्य क्षेत्रों में होने वाली नई पहल से सहायता प्राप्त है जिनका लक्ष्य है किसानों की आय को बढ़ाना। यह बजट ऐसी पहलों से भरा हुआ है जो वर्तमान में संकट के दौर से गुज़र रहे कृषि क्षेत्र को एक लाभदायक उद्यम में परिवर्तित कर सकती हैं।

यह मानना गलत होगा कि हमारे देश के नीति निर्माता इस बात से अनजान थे कि देश की ज्यादातर जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी और विभिन्न सरकारें अच्छी तरह से स्थापित किये गए महत्वाकांक्षी और प्राप्त किये जा सकने वाले लक्ष्यों के साथ इस क्षेत्र को प्राथमिकता देने के प्रयास करती दिखाई देती रही हैं। कृषि राज्यों का विषय होने के बावजूद केन्द्र सरकार को बहुत से लोगों की जीवन में सुधार लाने के लिए केंद्रीय क्षेत्र और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। भारत की प्रगति ग्रामीण भारत के विकास पर निर्भर है, जहां अधिकांश लोग रहते हैं और अपनी आजीविका की तलाश करते हैं। अभी तक सरकारों का दृष्टिकोण शहरी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने का रहा है जिससे अर्थव्यवस्था में असंतुलन और ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा हुई और कृषि संकट व किसानों की आत्महत्याएं इसके परिणाम हैं।

कृषि, किसान और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति दूरदर्शी दृष्टिकोण की कमी का परिणाम यह हुआ कि कृषि को लाभहीन मानकर बड़ी संख्या में लोगों ने खेती छोड़ दी और नौकरियों की तलाश में शहरों का रूख कर लिया। संतुलित और सतत आर्थिक विकास को हासिल करने में इस परिदृश्य को किसान समर्थक और गरीब समर्थक दृष्टिकोण के साथ बदलने की जरूरत महसूस की गई। ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में निवेश न केवल लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाता है बल्कि यह अर्थव्यवस्था की नींव को भी मजबूत करेगा और अर्थव्यवस्था के समग्र उच्च विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। अर्थव्यवस्था केवल तभी आगे बढ़ सकती है जब समाज में सबसे अधिक वंचित और पिछड़े लोगों को सशक्त बनाया जाएगा। शायद इसी दृष्टिकोण के साथ मोदी सरकार ने बजट में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रावधानों के जरिए ग्रामीण क्षेत्र में भारी निवेश करना शुरू कर दिया है।

पिछले तीन वर्षों के बजटों का उद्देश्य कृषि को एक उद्यम मानते हुए इसके प्रति समग्र दृष्टिकोण को बदलने का है जहां किसान अपने उत्पादन से अधिक लाभ कमा सकें। मुख्य रणनीति यह है कि किसी तरह किसानों को अच्छे दामों पर अपनी फसलों की बिक्री के लिए सशक्त बनाते हुए पूरी पर्यावरण-प्रणाली में सुधार करके कृषि के लिए इनपुट लागत को कम किया जा सके और किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके। देश ने लगभग 30 लाख टन फलों और सब्जियों के साथ लगभग 275 मिलियन टन का रिकार्ड अनाज उत्पादन हासिल किया है, लेकिन किसानों को ऐसे रिकॉर्ड उत्पादन का ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रभावी कदमों की आवश्यकता है। इस संदर्भ में किसानों को फसलों के लागत मूल्य से डेढ़ गुना ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए बजट

में की गई ऐतिहासिक घोषणा से कृषि को एक आकर्षक उद्यम बनाने में काफी मदद मिलेगी। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस निर्णय के प्रभाव का सार निम्नलिखित शब्दों में बतायाः

"मुझे यह घोषणा करते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है कि पूर्वनिर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, सरकार ने खरीफ की सभी अघोषित फसलों के लिए एमएसपी को उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुना रखने का फैसला किया है। मुझे विश्वास है कि यह ऐतिहासिक निर्णय हमारे किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।"

लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि इस ऐतिहासिक निर्णय का मुख्य लाभार्थी किसान ही हो। बढ़ी एमएसपी के मुकाबले फसलों की कीमत कभी-कभी कम भी रह सकती है और ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए किसानों को ऐसी प्रतिकूल स्थिति से बचाव

मोदी सरकार ने बजट में कीमत और मांग के पूर्वानुमान के लिए उचित नीतियों और व्यवस्थाओं के विकास के द्वारा एक संस्थागत तंत्र बनाने के लिए प्रावधान करते हुए किसानों द्वारा मूल्य आधारित निर्णय लेने पर विशेष जोर दिया है। 22000 ग्रामीण कृषि बाजारों एवं 585 कृषि उत्पाद विपणन समितियों के विकास और उन्नयन के लिए 2000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान छोटे और सीमांत किसानों को और सशक्त बनाएगा।

के लिए कोई सुरक्षा तंत्र तैयार करना होगा। इस तरह की स्थिति के लिए बजट में एक तंत्र बनाने के बारे में कहा गया है जिसके तहत एमएसपी और मौजूदा कम कीमतों के बीच के अंतर को किसानों को प्रदान किया जाएगा ताकि किसानों को इस प्रक्रिया में होने वाले किसी भी नुकसान से बचाया जा सके। ऐसे आश्वासन केवल एक ऐसी सरकार द्वारा ही दिये जा सकते हैं जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करना और किसानों को उनके लाभ के प्रति आश्वस्त करना हो। अगर सरकार इस तरह के तंत्र को विकसित करने में सक्षम है, तो कृषि क्षेत्र देश में तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बनने के लिए तैयार है।

सबसे बड़ी समस्या जो किसानों के सामने आती है वो है अपने उत्पाद की मार्केटिंग करना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम सुनिश्चित करने के लिए एमएसपी के कार्यान्वयन का तंत्र बनाने के अलावा मौजूदा कृषि विपणन प्रणाली में बड़े पैमाने पर बदलाव की आवश्यकता है। जहां एमएसपी खरीद एक सीमित भौगोलिक पहुंच के भीतर ही केवल कुछ चयनित वस्तुओं की मांग को पूरा करते हैं, वहीं कृषि विपणन कई नीतिगत विकृतियों से जूझता है, बड़ी संख्या में बिचौलियों के परिणामस्वरूप बिखराव होता है, बुनियादी ढ़ांचा कमजोर है, ऊर्ध्वाधर एकीकरण की कमी है और आधिकारिक मंडियां गड़बड़ी से जूझ रही हैं। बजट में कृषि उत्पाद विपणन समिति की पहुंच को मौजूदा 470 से बढ़ाकर 585 करते हुए ई-नाम को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए बजट में मौजूदा 22000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों में अपग्रेड करने का भी वादा किया गया है, जो ई-नाम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े होंगे और कृषि उत्पाद विपणन समितियों के नियमों से मुक्त होंगे जिससे किसान सीधे उपभोक्ताओं और थोक खरीददारों को अपना माल बेच सकेंगे। यह ऐसे छोटे और सीमांत किसानों को मजबूती देगा जो कृषि उत्पाद विपणन समिति और अन्य थोक बाजारों में सीधे लेनदेन करने की स्थिति में नहीं हैं। इससे करीब-करीब 86 प्रतिशत ऐसे किसानों का सशक्तिकरण होगा जो छोटे और सीमांत किसान हैं।

मोदी सरकार ने बजट में कीमत और मांग के पूर्वानुमान के लिए उचित नीतियों और व्यवस्थाओं के विकास के द्वारा एक संस्थागत तंत्र बनाने के लिए प्रावधान करते हुए किसानों द्वारा मूल्य आधारित निर्णय लेने पर विशेष जोर दिया है। 22000 ग्रामीण कृषि बाजारों एवं 585 कृषि उत्पाद विपणन समितियों के विकास और उन्नयन के लिए 2000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान छोटे और सीमांत किसानों को और सशक्त बनाएगा। यह ध्यान देने वाली बात है कि सभी बस्तियों को सड़कों के साथ जोड़ने का कार्य लगभग पूरा हो गया है और बस्तियों को कृषि और ग्रामीण बाजारों (ग्रामीण कृषि बाजार) से जोड़ने का विचार दूरगामी क्षेत्रों में रहने वाले किसानों की पहुंच में वृद्धि करेगा।

बजट में घोषित किए गए सबसे रचनात्मक निर्णयों में से एक है क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा देना। देश के कृषि क्षेत्रों को वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार पुनर्गठित करने की आवश्यकता है और विशिष्ट फसल वाले समूहों को वैज्ञानिक आधारों पर विकसित किया जा सकता है। औद्योगिक क्षेत्रों की तर्ज पर अपने विशिष्ट कृषि उत्पादन के अनुसार जिलों की पहचान करके उन्हें विकसित करने की घोषणा निश्चित रूप से देश में कृषि क्षेत्र की एक संगठित और योजनाबद्ध पुनर्रचना का कारण बनेगी। इससे पूरे क्षेत्र को आधुनिक बनाने और खाद्य प्रसंस्करण, संरक्षण, मूल्य संवर्धन, परिवहन और विपणन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने हेतु उत्पादन से विपणन तक एक चेन बनाने में भी मदद मिल सकती है।

मत्स्य पालन और पशुपालन करने वाले किसानों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा का विस्तार करना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं की समस्या का समाधान होगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसान

क्रेडिट कार्ड ने किसानों को काफी सशक्त बनाने के साथ-साथ उन्हें स्थानीय धन उधारदाताओं के कुचक्र से मुक्त कर दिया है और उन्हें काफी हद तक आत्मनिर्भर बना दिया है। मत्स्य पालन और पशुपालन के क्षेत्र में लगे किसान इस योजना के नए लाभार्थी हैं और इस योजना से उनकी उत्पादक क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा, मछली पालन करने वालों के लिए फिशरीज़ एंड ऐक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एफ़एआईडीएफ) और पशुपालन के क्षेत्र की ढांचागत आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए एनिमल हस्बेंडरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एएचआईडीएफ) की घोषणा आने वाले दिनों में इस क्षेत्र को निश्चित रूप से एक बड़ी छलांग के लिए तैयार करेगी। इसी तरह 1290 करोड़ के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय बैम्बू मिशन का पुनर्गठन न केवल बांस के किसानों की मदद करेगा बल्कि इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों का सृजन करते हुए पूरे कृषि क्षेत्र के किसानों की आय को बढ़ाने का एक नया रास्ता भी खोलेगा।

बजट में एक जीवंत, उत्तरदायी, बाजार उन्मुख और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कृषि पारिस्थितिक तंत्र के बारे में भी बात की गई है। कृषि से संबन्धित अन्य गतिविधियां, जैसे - बागवानी, डेयरी, मुर्गी पालन, सूअर पालन और छोटे पशुओं को पालने की गतिविधियां, किसानों की आय में काफी वृद्धि करने में सहायक हो सकती हैं।

सिंचाई के लिए सोलर पंप्स लगाने का निर्णय भी काफी अभिनव है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्साहजनक बात यह है कि इसका उपयोग किसानों के लिए अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए भी किया जा सकता है। यदि यह योजना वास्तव में काम करती है तो इससे वर्तमान में बिजली की समस्या का सामना कर रहे और उच्च लागत वाले डीजल पम्पिंग सेट व बिजली कटौती से जूझ रहे इस क्षेत्र में क्रांति आ सकती है। यह योजना न केवल बिजली की समस्या का समाधान करेगी बल्कि इससे उत्पादकता में भी वृद्धि होगी और बिजली वितरण कंपनियों को फालतू सौर ऊर्जा की बिक्री के जरिए किसान की आय में वृद्धि होगी।

ये कदम देश में एक नया कृषि पारिस्थितिक तंत्र बनाने में काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जहां कृषि क्षेत्र में स्थायी विकास के लिए दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता महसूस की जा रही है, वहीं उत्पादकता बढ़ाना भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि भारत अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर दिखाई देता है, फिर भी यह वैश्विक मानकों से मेल खाने वाले अधिकतम उत्पादकता के स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है। स्थिति को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि 40 प्रतिशत से कम भूमि में ही दूसरी फसल उगाई जाती है और कुछ राज्यों में तो यह केवल 25 फीसदी ही है। मोदी सरकार के सभी बजटों में सिंचाई, बीज, प्रौद्योगिकी और उच्च मूल्य वाले खेती उत्पादों जैसे फल, सब्जियां, दूध, अंडे, चिकन और मत्स्य पालन आदि पर ध्यान दिया गया है ताकि उत्पादकता को सतत तरीके से बढ़ाया जा सके। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रोप और प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जल विभाजन के विकास से सिंचाई में पानी के प्रभावी उपयोग के लिए एक बेहतर रूपरेखा का निर्माण हो रहा है। सिंचाई सुविधाओं के अलावा, ग्रामीण सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, फसल बीमा योजना के साथ-साथ मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजना से भारत में किसानों और ग्रामीण गरीबों को नया आत्मविश्वास और सुरक्षा मिल रही है।

बजट में एक जीवंत, उत्तरदायी, बाजार उन्मुख और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कृषि पारिस्थितिक तंत्र के बारे में भी बात की गई है। कृषि से संबन्धित अन्य गतिविधियां, जैसे - बागवानी, डेयरी, मुर्गी पालन, सूअर पालन और छोटे पशुओं को पालने की गतिविधियां, किसानों की आय में काफी वृद्धि करने में सहायक हो सकती हैं। भूमि और उसके दस्तावेजों का रखरखाव करने के पारंपरिक तरीकों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान और खेती के लिए भूमि के पट्टे के अभिनव तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने से कृषि क्षेत्र में आधुनिक तरीकों और तकनीक के इस्तेमाल के लिए रास्ता प्रशस्त हो सकता है। बजट में भूमि मालिकों के अधिकारों से समझौता किए बिना पट्टेदार किसानों को फसल ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में भी बात की गई है जिससे कृषि समुदाय के उन वर्गों के लिए अवसरों के नए दरवाजे खुलते हैं जो अब तक उपेक्षित रहे हैं। यह पट्टेदार किसानों को नए रास्ते तलाशने और खेती को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना सकता है।

तेजी से बदलते आर्थिक परिदृश्य में बजट में नीतिगत प्रयासों के साथ एक रणनीतिक रूपरेखा के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। अपने सभी आयामों से गरीबी को खत्म करने के भारतीय उद्देश्य से व्यापक रूप से निपटने के लिए इस बजट में न केवल कृषि क्षेत्र के लिए बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए भी एक परिवर्तनकारी एजेंडा है। यह स्वीकार करना होगा कि कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाए बिना आने वाले दो से तीन वर्षों में आठ प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि दर प्राप्त नहीं की जा सकती। और जैसा कि लगता है कि बजट में इस तथ्य को पहचाना गया है, एक वैकल्पिक आर्थिक दृष्टिकोण और बेहद जरूरी नीतिगत रूपरेखा के इसके दावे पर कोई विवाद नहीं हो सकता है। ■

भ्रम और भय फैलाना कांग्रेस की नीति बन गई है

रविशंकर प्रसाद

भ्रम और भय की राजनीति की उम्र लंबी नहीं होती। जनता न केवल इसे तुरंत समझ जाती है, बल्कि भ्रम और भय फैलाने वाले को सत्ता से बेदखल करने में जरा भी देर नहीं लगाती। नॉर्थ ईस्ट के तीन राज्यों में आए चुनावी नतीजों ने एक बार फिर ये बात स्पष्ट कर दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दो दिन पहले ही बहुत अच्छी बात कही कि, "भ्रम और भय फैलाने वालों, झूठ फैलाने वालों को सबसे अच्छा जवाब लोकतंत्र में मतदाता ही देते हैं और लोकतंत्र ने सारे झूठ को जवाब दे दिया है।"

नॉर्थ ईस्ट के तीनों राज्यों ने कांग्रेस की भ्रम और भय की राजनीति को नकार दिया है। आज नॉर्थ ईस्ट के दो राज्यों त्रिपुरा और नगालैंड में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। त्रिपुरा और नगालैंड में कांग्रेस पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई, जबकि मेघालय में जनता ने उसे सत्ता से बेदखल कर दिया।

कांग्रेस के पास आज मुद्दे नहीं है, वह जनता से पूरी तरह से कटी हुई है और सत्ता में आने के लिए नित नए तरीक़े ढूंढ़ती है। पिछले चार साल में कांग्रेस की एक नीति constant रही है और वह है अलग - अलग विषयों पर भ्रम फैलाना, लोगों में भय पैदा करना और इन विषयों की लिस्ट बहुत लंबी है।

एनपीए: एनपीए संकट इस देश को कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने अपने 10 वर्षों के शासन में अपने सभी करीबी उद्योगपतियों को लोन दिया, जनता की मेहनत का बैंकों में जमा धन से उन्हें मनमाफिक पैसा दिया और planning देखिए, बैंकों की बैलेंस शीट में उसे दिखाया भी नहीं, उन्हें छिपा दिया।

मार्च 2008 में बैंकों द्वारा दिया गया कुल एडवांस 18.06 लाख करोड़ रुपये था और UPA शासन के अगले 6 साल में, यह 3 गुना बढ़कर मार्च 2014 में 52.15 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। मार्च 2014 में, केवल 36% stressed assets को NPA के रूप में identify किया गया। जून 2017 में, stressed assets का खुलासा 82% पर पहुंच गया। मोदी सरकार ने भारी मात्रा में NPAs का पता लगाया जो अब तक छिपे हुए थे। हमने उनके 10 वर्षों के कारनामे को उजागर किया।

नीरव मोदी घोटाले की शुरुआत भी साल 2011 यूपीए शासन के दौरान ही हुआ था और आज कांग्रेस के लोग नीरव मोदी और चोकसी पर झूठ फैलाने के प्रयास कर रहे हैं। यह कौन नहीं जानता कि जतिन मेहता 2012 में कांग्रेस सरकार के समय बैंकों का हजारों करोड़ लेकर फरार हुआ था। आखिर किसने उस वक्त मदद की थी जतिन मेहता की। जबकि सच्चाई यह है कि मौजूदा सरकार के दौरान दो बार जतिन मेहता की संपत्ति अटैच की गई।

अभी कुछ दिन पहले तो हद ही हो गई जब कांग्रेस के ही एक और दामाद के द्वारा किसानों की गाढ़ी कमाई पर किए गए घोटाले के लिए भी कांग्रेस शोर मचाकर BJP सरकार पर आरोप लगाने लगी।

Fact – NPA दरअसल पूर्ववर्ती यूपीए सरकार का सबसे बड़ा घोटाला है। यह मौजूदा सरकार को UPA सरकार से मिली सबसे बड़ी Liability है। कांग्रेस अपने शासन काल में घोटालों की जो landmines बिछा के गई है, वो जब-जब फूटती है तो कांग्रेस शोर मचाकर जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश करती है।

13 अंकों का मोबाइल नंबर: एक मज़ेदार उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आप भी हंसेंगे कि कांग्रेस के जीवन में मुद्दे क्या है और वो देश की जनता को कितना मूर्ख समझते हैं।

कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने एक important topic पर सर्वे कराया। जानते हैं, विषय क्या था? उन्होंने सर्वे कराया कि मोबाइल नंबर 13 अंकों का होने वाला है और देश की जनता को बहुत परेशानी होने वाली है, इस पर आप अपनी राय दें।

Fact– इस सर्वे का लोगों में बहुत मजाक उड़ा, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। सच्चाई यह है कि 13 अंकों के नए नंबर सिम आधारित मशीन टू मशीन (M2M) संचार के लिए उपलब्ध कराए जाने हैं। इसका सामान्य मोबाइल नंबर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने इस बहाने आम लोगों में भ्रम और भय फैलाने की कोशिश की।

दरअसल कांग्रेस हमेशा ही टेक्नोलॉजी का जनता-जनार्दन के कल्याण के लिए उपयोग के विरुद्ध रही है चाहे वो DBT हो या AADHAR। क्योंकि उन्हें पता है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग दलाली की दुकानें बंद कर देता है।

आज मोदी सरकार टेक्नोलॉजी से हर भारतीय को जोड़ना चाहती है। सरकारी सेवाओं का लाभ सीधा जनता तक पहुंचे इसके लिए बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है तब कांग्रेस टेक्नॉलोजी के बारे में भ्रम फैलाकर जनता के बीच भय पैदा करना चाहती है।

FRDI (Financial Resolution and Deposit Insurance) Bill: FRDI का जो बिल अभी चर्चा में ही है, जिस पर अभी काम चल ही रहा है, उसको लेकर भी कांग्रेस ने अफवाह फैलाने और जनता को भ्रमित करने की कोशिश की, जबकि यह बिल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जनता का पैसा सुरक्षित रहे।

Fact – जो बिल अभी प्रक्रिया में ही है, उस पर सवाल उठाकर

कांग्रेस ने खुद को ही कठघरे में खड़ा किया है।

Bank convenience Charges: इसको लेकर भी कांग्रेस ने जनता के बीच अफवाह फैलाई कि बैंक लोगों के खातों पर Convenience fee charge करेगी, बैंकों की services महंगी हो जाएंगी। पूरे WhatsApp को झूठे और भ्रामक messages से भर दिया।

Fact – कांग्रेस की फैलाई गई ये अफवाह भी गलत, आधारहीन और झूठी थी। सच्चाई यह है कि ऐसी कोई चर्चा तक नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के गरीबों को बैंकों से जोड़ने का एक अभूतपूर्व काम किया, जबकि कांग्रेस बैंकों पर अविश्वास पैदा करने की कोशिश करती रही।

डोकलाम: कांग्रेस ने डोकलाम में चीनी सेना की भारी उपस्थिति को लेकर प्रेस कांफ्रेंस कर ऐसा चित्र खड़ा करने की कोशिश की, जैसे चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया हो और भारत की हालत खराब है। आज हम भी यहीं हैं और आप भी यहीं हैं। डोकलाम में जो कुछ हो रहा

एक मज़ेदार उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आप भी हंसेंगे कि कांग्रेस के जीवन में मुद्दे क्या है और वो देश की जनता को कितना मूर्ख समझते हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने एक important topic पर सर्वे कराया। जानते हैं, विषय क्या था? उन्होंने सर्वे कराया कि मोबाइल नंबर 13 अंकों का होने वाला है और देश की जनता को बहुत परेशानी होने वाली है, इस पर आप अपनी राय दें।

है, पूरा देश देख रहा है।

Fact – डोकलाम मुद्दे पर पहली बार पूरे विश्व ने देखा कि भारत ने अपना लोहा मनवाया। चीन को अपने कदम पीछे खींचने पड़े।

कांग्रेस देश के गौरव को, देश के आत्म-विश्वास को भी दांव पर लगाकर भ्रम और भय फैलाना चाहती है।

राफेल डील: राफेल डील पर हर रोज कांग्रेस का नया झूठ बाहर आता है। वो परिवार जिसने defence deals में सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार किया है जिसे पूरा देश जानता है और ऐसे लोग अब राफेल पर सवाल उठा रहे हैं।

Fact – सच यह है कि कांग्रेस ने 10 सालों तक राफेल डील को लटकाकर देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया, लेकिन सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह डील हमने न केवल प्राप्त की, बल्कि देश के करोड़ों रुपये भी बचाए। राफेल विमान की कीमत कांग्रेस शासन में हुए सौदे के अनुपात में काफी कम है।

कांग्रेस देश की सुरक्षा और सेना के मनोबल को दांव पर लगाकर कांग्रेस भ्रम और भय फैलाना चाहती है।

GST: भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व ने GST को भारत में आर्थिक क्रांति के रूप में माना। GST लागू होने के बाद गरीबों, निम्न मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्गीय परिवारों को बहुत बड़ा लाभ हुआ है। देश के व्यापारी tax terrorism से मुक्त हुए हैं।

लेकिन GST को लेकर पिछले 8 महीनों में कांग्रेस ने व्यापारियों में भ्रम और भय फैलाकर इस बात के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है कि देश में GST fail हो जाए।

Fact - जीएसटी ने देश के पूरे टैक्स सिस्टम को सरलतम बनाया। सरकार को जहां भी सुधार की आवश्यकता दिखी, उसने आगे बढ़कर वो सुधार किए। आम उपभोक्ता वस्तुओं के लिए कम से कम टैक्स देना पड़े, सरकार ने यह सुनिश्चित करने का काम किया है।

नोटबंदी: जब हमने देश हित में, हमारे गरीबों के हितों के लिए नोटबंदी का निर्णय लिया, पूरे देश ने हमारा साथ दिया लेकिन कांग्रेस और कुछ चुनिंदा लोगों को जब इसका नुकसान हुआ तो उन्होंने जनता के बीच भ्रम फैलाना शुरू कर दिया, लोगों को बरगलाना शुरू कर दिया।

नोटबंदी के समय राहुल गांधी जी ने एक फोटो ट्वीट की, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति बैंक की लाइन में लगा रो रहा था और कहा गया कि ये बुजुर्ग नोटबंदी से पीड़ित होकर रो रहा है जबकि सच्चाई क्या थी, पूरे देश ने देखा। उन्होंने मीडिया को खुद बताया कि जब वह बैंक के बाहर कतार में खड़े थे तो किसी ने उन्हें धक्का दे दिया। इस क्रम में एक महिला ने उनके पैर कुचल दिए थे और इसलिए वे रो रहे थे न कि नोटबंदी के कारण।

कांग्रेस के सहयोगी दल NCP के मजीद मेनन ने कहा कि नीरव मोदी ने 8 नवंबर, 2017 से पहले बैंक में सारे पैसे जमा कर दिए थे, क्योंकि उन्हें नोटबंदी का पहले से पता था। अब उन्हें कौन याद दिलाए कि नोटबंदी 8 नवंबर, 2016 को हुआ था।

नोटबंदी के दौरान जब पूरा देश एकजुट होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान को आगे बढ़ा रहा था, तब कांग्रेस गरीबों की आड़ में खुद के काले धन को सफ़ेद करने के लिए देश में भ्रम और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही थी।

Fact – नोटंबदी को लेकर कांग्रेस के सारे आरोप गलत साबित हुए हैं। इसका असर उसे उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के चुनावों में भुगतना भी पड़ा है। सच्चाई यह है कि नोटबंदी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सशक्त कदम साबित हुआ है। नोटबंदी का एक बड़ा असर यह भी हुआ कि देश डिजिटल लेन-देन की ओर तेजी से आगे बढ़ा है।

कांग्रेस को समझना होगा कि लोकहित के कार्यों में, देश की सुरक्षा से जुड़े विषयों में, आर्थिक क्षेत्र में हो रहे reforms के बारे में आए दिन भ्रम और भय फैलाने की उनकी राजनीति को देश अच्छी तरह जानता है और जनता जनार्दन लगातार जवाब भी उन्हें दे रही है। ■

(लेखक वरिष्ठ भाजपा नेता एवं केन्द्रीय मंत्री हैं)

मंत्रिमंडल ने भगौड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 1 मार्च को संसद में भगौड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 को रखने के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी। इस विधेयक में भारतीय न्यायालयों के कार्यक्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानूनी प्रक्रिया से बचने वाले आर्थिक अपराधियों की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कड़े उपाय करने में मदद मिलेगी। ऐसे अपराधों में कुल 100 करोड़ रुपए अथवा अधिक मूल्य के ऐसे अपराध इस विधेयक के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आएंगे।

इस विधेयक से भगौड़ा आर्थिक अपराधियों के संबंध में कानून के राज की पुनर्स्थापना होने की संभावना है, क्योंकि इससे उन्हें भारत वापस आने के लिए बाध्य किया जाएगा और वे सूचीबद्ध अपराधों का कानूनी सामना करने के लिए बाध्य होंगे। इससे ऐसे भगौड़ा आर्थिक अपराधियों द्वारा की गई वित्तीय चूकों में अंतर्विष्ट रकम की उच्चतर वसूल करने में बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं को भी मदद मिलेगी और ऐसी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।

यह आशा की जाती है कि भगौड़े अपराधियों द्वारा भारत और विदेशों में उनकी संपत्तियों को तेजी से जब्त करने के लिए उन्हें भारत लौटने और सूचीबद्ध अपराधों के संबंध में कानून का सामना करने के लिए भारतीय न्यायालयों के समक्ष पक्ष रखने के लिए एक विशेष तंत्र का सृजन हो सकेगा।

विधेयक की मुख्य-मुख्य बातें

- किसी व्यक्ति के भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित होने पर विशेष न्यायालय के समक्ष आवेदन करना
- अपराध के जरिए भगौड़ा आर्थिक के रूप में घोषित व्यक्ति की संपत्ति को जब्त करना
- भगौड़ा आर्थिक अपराधी होने के आरोपित व्यक्ति को विशेष न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करना
- अपराध के फलस्वरूप व्युत्पन्न संपत्ति के चलते भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति की संपत्ति को जब्त करना
- ऐसे अपराधी की बेनामी संपत्ति सहित भारत और विदेशों में अन्य संपत्ति को जब्त करना
- भगौड़े आर्थिक अपराधी को किसी सिविल दावे का बचाव करने से अपात्र बनाना और
- अधिनियम के अंतर्गत जब्त की गई संपत्ति के प्रबंधन व निपटान के लिए एक प्रशासन की नियुक्ति की जाएगी।

तथापि, ऐसे मामले में जहां किसी व्यक्ति के भगौड़ा घोषित होने के पूर्व किसी भी समय कार्यवाही की प्रक्रिया के समानांतर भगौड़ा आर्थिक अपराधी भारत लौट आता है और सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश होता है, तो उस स्थिति में प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत कानूनन कार्यवाही रोक दी जाएगी। सभी आवश्यक संवैधानिक रक्षा उपाय जैसे अधिवक्ता के माध्यम से व्यक्ति को सुनवाई का अवसर, उत्तर दाखिल करने के लिए समय प्रदान करना, उसे भारत अथवा विदेश में समन भिजवाना तथा उच्च न्यायालय में अपील करने जैसे प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, कानूनी प्रावधानों के अनुपालन में संपत्ति के प्रबंधन व निपटान के लिए प्रशासन की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है।

आर्थिक अपराधियों के ऐसे अनेक मामले घटित हुए हैं जहां भारतीय न्यायालयों को न्याय क्षेत्र से भागने, आपराधिक मामलों के शुरुआत की प्रत्याशा अथवा मामले अथवा आपराधिक कार्यवाही को लंबित करने के दौरान आर्थक अपराधी भाग निकला है। भारतीय न्यायालयों के ऐसे अपराधियों की अनुपस्थिति का कारण अनेक विषय परिस्थितियां उत्पन्न हुई हो, जैसे प्रथमत: इससे आपराधिक मामलों में जांच रुक सी जाती है। दूसरे, इससे न्यायालयों का मूल्यवान समय बर्बाद होता है। तीसरे, इससे भारत में कानून के राज का अवमूल्यन होता है।

नीति का क्रियान्वयन व लक्ष्य

वर्तमान कानूनों में व्याप्त कमियों के परिहार व भारतीय न्यायालयों के कार्यक्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानूनों की प्रक्रिया से बचने वाले आर्थिक अपराधियों की प्रवृत्ति के निरोधात्मक तय करने के दृष्टिगत,

यह विधेयक प्रस्तावित किया जा रहा है। इस विधेयक में किसी व्यक्ति को भगौड़ा आर्थिक अपराधी के रूप में घोषित करने के लिए इस विधेयक में एक न्यायालय (धन-शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 के अंतर्गत विशेष न्यायालय) का प्रावधान किया गया है।

दरअसल, भगौड़ा आर्थिक अपराधी एक ऐसा व्यक्ति है, जिसके विरुद्ध किसी सूचीबद्ध अपराध के संबंध में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा चुका है और जिसने आपराधिक कार्यवाही से बचने के लिए भारत छोड़ दिया है अथवा विदेश में रह रहा है और आपराधिक अभियोजन का समाना करने के लिए भारत लौटने से इंकार कर रहा है। आर्थिक अपराधों की सूची को इस विधेयक की तालिका में अंतर्विष्ट किया गया है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे मामले में न्यायालयों पर कार्य का ज्यादा भार न पड़े, केवल उन्हीं मामलों की इस विधेयक की परिसीमा में लाया गया है, जहां ऐसे अपराधों में कुल 100 करोड़ रुपए या अधिक की राशि अन्तर्विष्ट हो।

पृष्ठभूमि

आर्थिक अपराधियों के ऐसे अनेक मामले घटित हुए हैं जहां भारतीय न्यायालयों को न्याय क्षेत्र से भागने, आपराधिक मामलों के शुरुआत की प्रत्याशा अथवा मामले अथवा आपराधिक कार्यवाही को लंबित करने के दौरान आर्थक अपराधी भाग निकला है। भारतीय न्यायालयों के ऐसे अपराधियों की अनुपस्थिति का कारण अनेक विषय परिस्थितियां उत्पन्न हुई हो, जैसे प्रथमतः इससे आपराधिक मामलों में जांच रुक सी जाती है। दूसरे, इससे न्यायालयों का मूल्यवान समय बर्बाद होता है। तीसरे, इससे भारत में कानून के राज का अवमूल्यन होता है।

इसके अलावा, आर्थिक अपराध के अधिकांश ऐसे मामलों में बैंक ऋणों की गैर-अदायगी शामिल होती है, जिससे भारत के बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय स्थिति बदतर हो जाती है। इस समस्या की गंभीरता से निपटने के लिए कानून के वर्तमान सिविल और आपराधिक प्रावधान पूर्णतः पर्याप्त नहीं हैं। अतएव, ऐसी कार्यवाहियों की रोकथाम सुनश्चित करने के लिए प्रभावी, तीव्रतम और संवैधानिक दृष्टि में मान्य प्रावधान किया जाना आवश्यक समझा गया है।

यहां उल्लेखनीय है कि भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में गैर-दोषसिद्धि-आधारित संपत्ति के जब्त करने की प्रवृत्ति अपराध के प्रति यूनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन (भारत द्वारा 2011 में मान्य) से अनुसमर्थित है। विधेयक में इसी सिद्धांत को अंगीकार किया गया है। उपरोक्त संदर्भ के मद्देनजर, सरकार द्वारा बजट 2017-18 में यह घोषणा की गई थी कि सरकार विधायी संशोधन लाने अथवा जब तक ऐसे अपराधी समुचित विधि न्यायालय मंच के समक्ष समर्पण नहीं करता, ऐसे अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने के लिए नया कानून तक लाया जाएगा। ■

2014-2015 से 2016-2017 के दौरान जनजातीय उप योजना के तहत 62947.82 करोड़ खर्च किए गये

पिछले कई वर्षों के दौरान जनजातीय उप-योजना (टीएसपी), जिसे अब अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) भी कहा जाता है, के तहत आवंटन और व्यय लगातार बढ़ रहा है। जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह भाभोर ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर यह जानकारी दी कि पिछले तीन वर्षों 2014-15 से 2016-17 तक कुल 35 विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने 62947.82 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया। 2014-2015 के दौरान 19920.72 करोड़ रुपये, 2015-2016 के दौरान 21216.54 करोड़ रुपये खर्च किए गए और 2016-2017 के दौरान 21810.56 करोड़ रुपये खर्च किए गये। सभी मंत्रालयों में से 2014-15 के दौरान स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सबसे ज्यादा 4707.15 करोड़ खर्च किए, उसके बाद जनजातीय कार्यों में 3832.20 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण विकास में 3314.27 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

2015-2016 और 2016-2017 के दौरान, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सबसे अधिक राशि क्रमशः 4472.26 करोड़ और 4793.96 करोड़ रुपये खर्च किए, उसके बाद स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने टीएसपी में (क्रमशः 4287.24 करोड़ और 4343.98 करोड़ रुपये) खर्च किए। जनवरी, 2017 में बिजनेस नियमों का आवंटन (एबीआर) संशोधित किया गया है जिसके तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) को केन्द्रीय मंत्रालयों के अनुसूचित जनजातीय घटक (एसटीसी) निधियों की निगरानी की जिम्मेवारी दी गई है जिसकी रूपरेखा नीति आयोग द्वारा तैयार की गई है। मंत्रालय ने 2017 से ही ऑनलाइन निगरानी प्रणाली http://stcmis.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है। इस ढांचे में योजनाओं के तहत एसटी के कल्याण के लिए आवंटन की निगरानी की गई है, आवंटन के जरिए व्यय की निगरानी, शारीरिक प्रदर्शन और परिणाम निगरानी की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, समन्वय और निगरानी के लिए लाइन मंत्रालयों / विभागों में नोडल अधिकारी भी नामित किए गए हैं। मंत्रालय/विभागवार प्रदर्शन की समीक्षा संयुक्त रूप से एमओटीए और नीति आयोग द्वारा की जाएगी। जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के तहत योजनाओं का कार्यान्वयन की पूरी जिम्मेदारी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों और राज्य सरकारों की है। ■

केंद्र सरकार किसानों की भलाई के लिए कटिबद्ध है : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 26 फरवरी को कर्नाटक के अपने सांगठनिक प्रवास के दूसरे दिन हुम्नाबाद स्थित वीरभद्रेश्वरा फंक्शन हॉल में गन्ना किसानों से विचार-विमर्श किया। श्री शाह ने राज्य की बदहाली के लिए कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार पर जमकर प्रहार किया। इसके बाद, श्री शाह ने यादगिरी जिले की सुरापुर स्थित सज्जन लेआउट में सुरापुर और यादगिरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के नवशक्ति समावेश को संबोधित किया और फिर सेदाम तालुका के श्री मनिकेश्वरी मठ में कोली समुदाय से संवाद किया। अपने व्यस्त कार्यक्रमों में भाजपा अध्यक्ष ने जहां गुलबर्गा के एनवी मैदान में अनुसूचित जाति सम्मलेन को संबोधित किया। वहीं पीडीए इंजीनियरिंग कॉलेज ऑडिटोरियम में व्यापारियों और उद्योगपतियों से भी संवाद स्थापित किया। इन सभी कार्यक्रमों से पूर्व उन्होंने बीदर के रेकुल्गी स्थित बुद्ध विहार में भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद, मंगाल्गी गांव में आत्महत्या करने वाले कृषक स्वर्गीय शिवराज बासालिंगप्पा अलरेड्डी के घर उनके शोक-संतप्त परिवारजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना भी दीं।

कर्नाटक के गन्ना किसान बहुल क्षेत्र हुम्नाबाद में किसानों से परिसंवाद स्थापित करने के दौरान भाजपा अध्यक्ष ने किसानों की समस्याएं सुनीं और केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा देश के किसान कल्याण के लिए उठाये गए महत्वपूर्ण क़दमों का विस्तार से उल्लेख भी किया. किसानों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्त्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों की भलाई व उनके जीवन के उत्थान के लिए कटिबद्ध है और पिछले चार सालों में मोदी सरकार ने इसे चरितार्थ करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि देश के गन्ना किसानों को उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने चीनी के रॉ मटेरियल के आयत पर प्रतिबन्ध लगाया। साथ ही, औद्योगिक उद्देश्य के लिए आयात होने वाली चीनी के रॉमटेरियल पर इम्पोर्ट ड्यूटी को बढाकर पहले साल में ही 40% किया और अब इसे बढ़ाकर 100 % कर

दिया है। गन्ना के सह-उत्पाद इथेनोल को पेट्रोल में 10 फीसदी मिलाना भी हमने अनिवार्य किया, ताकि किसानों का इथेनोल बिक सके और उन्हें इसकी उचित कीमत मिल सके। इसके अतिरिक्त, इथेनोल की जो कीमत पहले 11 रूपये के आसपास होती थी उसकी कीमत 48 रुपये तक लाने का काम भी हमारी सरकार ने किया ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो।

भाजपा शासित राज्यों में उप्र का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि वहां के गन्ना किसानों को गन्ने का भुगतान गन्ने की बुवाई के 90 दिन के भीतर करने का क़ानून वहां की राज्य सरकार ने अमल में लाया और वर्तमान सीजन में किसानों के सभी पैसों का भुगतान हो गया है तथा पुराना बकाया भी काफी हद तक समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद सीधा किसानों के खातों में 6 हज़ार करोड़ का बकाया भी भेजने का काम भाजपा सरकार ने किया है।

श्री शाह ने उपस्थित किसानों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि यदि कर्नाटक में भाजपा की सरकार बनी तो यहां बन्द पड़ी चीनी मिलों को अविलम्ब शुरू किया जाएगा और उप्र की तर्ज पर कर्नाटक के चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को 90 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। केंद्र की पूर्व यूपीए सरकार पर तंज कसते हुए श्री शाह ने कहा कि यूपीए काल में दलहन का आयात कर कमीशन खाई जाती थी, जबकि केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद हमने दलहन की बुवाई बढ़ाई और उसे एमएसपी पर खरीदने की पद्धति की शुरुआत भी की। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि किसानों को उनकी लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का साहस आज से पहले किसी भी सरकार ने नहीं किया। कांग्रेस सरकारें किसानों के नाम पर वोट लेकर सत्ता में आती रही, लेकिन किसी ने किसानों के लिए डेढ़ गुना समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी ने बजट में किसानों को लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का निर्णय लिया, जो किसानों की आय को दुगुना करने के लक्ष्य की दिशा में विशिष्ट कदम है। उन्होंने कहा कि कई ऐसी योजनाएं हैं जो राज्य सरकार के सहयोग के बिना किसानों तक नहीं पहुंचाई जा सकती, लेकिन केंद्र की किसान कल्याणकारी योजनाओं को कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार जनता तक पहुंचने ही नहीं देती। श्री शाह ने कहा कि आजादी के बाद से ही देश के किसानों को यूरिया की कमी से जूझना पड़ता था लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने यूरिया को नीम कोटेड करने की पहल की जिससे इसकी कालाबाजारी रुकी और किसानी को राहत मिली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत देश के 16 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा पहुंचाने का प्रबंध है, लेकिन सिद्धारमैया सरकार द्वेषवश इसे जमीनी स्तर पर कार्यान्वित नहीं कर रही है। श्री शाह ने उपस्थित किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि यदि कर्नाटक में भाजपा की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के द्वारा राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ढाई गुना सिंचाई सुविधा बढ़ाने की कार्ययोजना पर हमारी सरकार काम करेगी। श्री शाह ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले पचास साल में पहली बार इस योजना को वैज्ञानिक तरीके से बनाने का प्रयास किया गया है और इसमें जो भी खामियां हंम उस पर सांसदों से राय मांगी गयी हैं। साथ ही, इसकी प्रक्रिया को सुधारने के लिए एक कमिटी भी गठित की गयी और संभवतः चार-पांच माह में यह योजना अपने नए स्वरूप में लागू हो जायेगी, जिसके अंतर्गत हर किसान को उनकी फसल का बीमा मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि बाढ़ या सूखा के कारण पहले किसानों को जो राहत-राशि दी जाती थी उसे भाजपा की सरकार ने सत्ता में आने के पहले साल ही दो गुना किया और 1 हक्टेयर की जगह 4 हेक्टेयर भूमि तक मदद करने की व्यवस्था भी की।

यूपीए काल में दलहन का आयात कर कमीशन खाई जाती थी, जबकि केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद हमने दलहन की बुवाई बढ़ाई और उसे एमएसपी पर खरीदने की पद्धति की शुरुआत भी की। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि किसानों को उनकी लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का साहस आज से पहले किसी भी सरकार ने नहीं किया।

श्री शाह ने कहा कि 27 फरवरी को कर्नाटक में किसान सम्मलेन होने वाला है जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं मौजूद रहेंगे। इसके बाद भाजपा के कार्यकर्ता हर किसान के घर जाकर एक मुट्ठी चावल लेकर खिचड़ी बनाकर यह प्रतिज्ञा लेते हुए वो अन्न ग्रहण करेंगे कि कर्नाटक की जो अगली भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी वह किसानों को समर्पित और किसानों के लिए काम करने वाली सरकार होगी। भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के झूठे आरोपों का करार जवाब देते हुए कहा कि केंद्र में नरेन्द्र मोदी सरकार आने के बाद किसी भी उद्योगपति का कर्ज माफ़ नहीं किया गया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनके पास इससे सम्बंधित कोई रिकॉर्ड हो तो उसे सार्वजनिक करें, मैं उसका जवाब देने और कर्नाटक के किसानों से माफ़ी मांगने को तैयार हूं। ■

'हर मोर्चे पर विफल है कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 26 फरवरी को कर्नाटक के व्यस्ततम सांगठनिक प्रवास के तीसरे और अंतिम दिन गुलबर्ग में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और राज्य की बदहाली के लिए कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार पर जम कर प्रहार किया। श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक के युवा कांग्रेस कांग्रेस की भ्रष्ट सिद्धारमैया सरकार को श्री डी (3D) से पारिभाषित कर रहे हैं, श्री डी अर्थात् धोखा, दादागिरी और डायनेस्टी पॉलिटिक्स। असल में कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार का यही चरित्र है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कर्नाटक में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का उत्साह है और यह निश्चित है कि राज्य में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के हर क्षेत्र में भाजपा को अभूतपूर्व जनसमर्थन मिल रहा है, इसका कारण यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार 5 साल में हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया सरकार लगातार भ्रष्टाचार के नये कीर्तिमान स्थापित करती जा रही है और वह इसे अपने मेडल के रूप में पेश करने से भी नहीं हिचकती। भ्रष्टाचार और कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार एक-दूसरे के पर्याय बन गये हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस का कुशासन कैसा होता है, यह देखना है तो कांग्रेस की तरफ से पांच दशकों तक कर्नाटक में राजनीति करने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लोक सभा क्षेत्र को देखिये, इतना पिछड़ा हुआ इलाका आपको कर्नाटक में कहीं और नहीं दिखाई देगा।

कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार पर करारा प्रहार करते हुए श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से केस की मेरिट में गये बिना PFI और SDPI पर से सभी केस विड्रा किये, यह एक घोर असंवैधानिक प्रकिया है और एकतरफा कार्रवाई है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार के शासनकाल में कर्नाटक में 3781 किसानों ने आत्महत्या की है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है लेकिन सिद्धारमैया सरकार के माथे पर जूं भी नहीं रेंगती। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या को दूर करने के लिए काम करने के बजाय सिद्धारमैया सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि मैं कल ऐसे तीन मृतक किसान परिवार से मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार किसानों की आत्महत्या को लेकर कतई गंभीर नहीं है। साथ ही, पीड़ित परिवार के प्रति उसका रवैया काफी असंवेदनशील है, यह निंदनीय है, मैं कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार की इस संवेदनहीनता की घोर भर्त्सना करता हू। उन्होंने कहा कि बहुत समय

से यहां के किसानों की मांग है कि BSSK शुगर मिल को फिर से शुरू किया जाय। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि किसानों की इस मांग को हम अपने घोषणा पत्र में शामिल शामिल करेंगे और इस समस्या का पूरा समाधान करेंगे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद से विकास ठप्प पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि 13वें वित्त आयोग में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने कर्नाटक को जहां केवल 88,583 करोड़ रुपये दिए थे, वहीं 14वें वित्त आयोग में मोदी सरकार ने कर्नाटक सरकार को 2,19,506 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं जो यूपीए सरकार की तुलना में लगभग ढाई गुना ज्यादा है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त उज्जवल डिस्कॉम योजना के लिए लगभग 4,300 करोड़, डिस्ट्रिक्ट मिनिरल फंड के तौर पर 34,353 करोड़, स्मार्ट सिटी के लिए 960 करोड़, अमृत योजना के लिए 4,953 करोड़, स्वच्छ भारत अभियान के लिए 204 करोड़, बस खरीद के लिए 239 करोड़, बेंगलुरु मेट्रो के लिए 2600 करोड़, स्वायल हेल्थ कार्ड के लिए 31 करोड़, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए 405 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 219 करोड़, नये सड़कों-हाइवे के निर्माण के लिए 50 प्रोजेक्ट्स हेतु लगभग 27 हजार करोड़ रुपये और राज्य में रेलवे के विकास के लिए 2197 करोड़ रुपये दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह कर्नाटक को 14वें वित्त आयोग की अनुदान राशि के अलावा विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं में 1,17,000 करोड़ रुपये और अधिक मिले हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत राज्य में 6.15 लाख गैस कनेक्शन वितरित किये गए हैं। साथ ही, लगभग पौने दो करोड़ LED बल्ब भी वितरित किये गये हैं।

श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक की जनता हर मोर्चे पर विफल कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार को बदलने के लिए तैयार बैठी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और कर्नाटक में श्री येदुरप्पा जी के नेतृत्व में चुनाव जीतने के लिए तैयार है। ■

'भाजपा सरकार देश के ओबीसी समाज और पिछड़े समाज के कल्याण के लिए कटिबद्ध'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 26 फरवरी को गुलबर्ग, कर्नाटक में ओबीसी समुदाय के विशाल कन्वेंशन को संबोधित किया और कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार देश के ओबीसी समाज और पिछड़े समाज के कल्याण के लिए कटिबद्ध है, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ओबीसी समाज के उत्थान की राह में रोड़े अटकाने का काम कर रही है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के पक्ष में पूरे कर्नाटक में जिस प्रकार का माहौल है। उससे यह स्पष्ट है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के हर वर्ग के लोगों की जुबान पर एक ही बात है कि सिद्धारमैया सरकार को जाना चाहिए और येदुरप्पा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार को आना चाहिए।

श्री शाह ने कहा कि अन्य पार्टियां अपने नेताओं और सभाओं के आधार पर चुनाव मैदान में उतरती होंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव में जाती है तो उसका आधार केवल बूथ कार्यकर्ता ही होते हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक भाजपा ने हर बूथ पर संगठन को खड़ा करने और उसे मजबूत करने का काम किया है, कार्यकर्ताओं को तैयार किया है इसलिए कर्नाटक भाजपा का नेतृत्व अभिनंदन के पात्र हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के ओबीसी समुदाय के उत्थान के लिए एक-के-बाद-एक कई कदम उठाये गये, जबकि कांग्रेस ने एक-के-बाद-एक ओबीसी समुदाय के कल्याण कार्यों का विरोध किया, इससे यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ओबीसी समाज के हितैषी हैं जबकि कांग्रेस ओबीसी विरोधी है। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया जी ओबीसी समाज का हितैषी होने का दावा करते हैं, लेकिन जब ओबीसी समाज के लिए काम करने की बात आती है तो उन्हें माइनॉरिटी के अलावे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब ओबीसी समाज को आगे ले जाने की बात करती है तो यह कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट भर नहीं है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का सिद्धांत ही है - "सबका साथ, सबका विकास" और इसका मतलब है समाज के अंतिम व्यक्ति को विकास की प्रथम पंक्ति में लाना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा पिछले चार सालों में लिए गये हर निर्णय के केंद्र में देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी और ओबीसी समाज ही हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक लगभग 3.80 लाख गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा ओबीसी समाज को ही मिला है, इसी तरह शौचालय के रूप में स्वच्छता अभियान का भी सबसे ज्यादा फायदा देश के पिछड़े वर्ग और ओबीसी समाज को ही मिला है।

श्री शाह ने कहा कि वर्षों से ओबीसी समुदाय की यह मांग थी कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दिए जाने की मांग 1955 से लगातार हो रही थी, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई प्रयास नहीं

किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का विधेयक लेकर संसद में आई थी लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपना असली चेहरा उजागर करते हुये और ओबीसी समाज का विरोध करते हुये इस विधेयक को राज्य सभा में पारित नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया जी ओबीसी समाज का हितैषी होने का दावा करते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि कांग्रेस द्वारा ओबीसी समुदाय का अपमान करने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सिद्धारमैया जी का क्या कहना है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक तरफ तो ओबीसी समुदाय की भलाई की बात करती है, वहीं दूसरी तरह ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता प्रदान नहीं करने देती, यह दोहरा चरित्र है कांग्रेस का।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार देश के पिछड़े और ओबीसी समाज के कल्याण के लिए कई योजनायें लेकर आई है,

मोदी सरकार ने फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से डेढ़ गुना करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है, जो किसानों की आय को 2022 तक दुगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सबसे महत्त्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने फसलों के समर्थन मूल्य को लागत मूल्य का डेढ़ गुना करने का साहस दिखाया है, इसका भी सबसे ज्यादा फायदा ओबीसी समाज को होगा।

लेकिन कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार कर्नाटक में इन योजनाओं को नीचे तक नहीं पहुंचने देती। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना का सबसे ज्यादा फायदा देश के गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज के लोगों को हुआ है। उन्होंने कहा कि हम जब मुद्रा योजना लेकर आये तो कांग्रेस अध्यक्ष और पी. चिदंबरम इसका मखौल उड़ा रहे थे। बोलते थे कि पांच लाख तक के लोन से क्या होगा, लेकिन आज देखिये कैसे देश के गरीबों की जिन्दगी बदल रही है। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी कांग्रेस सरकार ने बैंकों के दरवाजे देश की गरीब जनता के लिए खुलने नहीं दिए, आज हमने इसकी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अकेले कर्नाटक में मोदी सरकार की इस योजना से 98 लाख अर्थात् लगभग एक करोड़ युवाओं को 39 हजार करोड़ रुपये का लोन दिया गया है, जबकि देश में 9 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हुये हैं।

श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से डेढ़ गुना करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है, जो किसानों की आय को 2022 तक दुगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सबसे महत्त्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने फसलों के समर्थन मूल्य को लागत मूल्य का डेढ़ गुना करने का साहस दिखाया है, इसका भी सबसे ज्यादा फायदा ओबीसी समाज को होगा।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश के हर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसको साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने देश के लगभग 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए पांच लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था की है, जिससे देश के लगभग 50 करोड़ लोगों को बेहतर स्वास्थ्य का फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीबों, पिछड़ों, दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज के लोगों के लिए वरदान साबित होने वाली है।

श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक में परिवर्तन करने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ओबीसी समुदाय की है। उन्होंने कहा कि यदि कर्नाटक का पिछड़ा वर्ग और ओबीसी समाज तय कर ले, तो कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार को कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने ओबीसी समुदाय का आह्वान करते हुए कहा कि कांग्रेस को कर्नाटक से उखाड़ फेंकने का काम ओबीसी समाज को करना है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मोदी सरकार ने चार सालों में कर्नाटक के लिए क्या किया है। उन्होंने कहा कि 13वें वित्त आयोग में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने कर्नाटक को जहां केवल 88,583 करोड़ रुपये दिए थे, वहीं 14वें वित्त आयोग में मोदी सरकार ने कर्नाटक सरकार को 2,19,506 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं जो यूपीए सरकार से लगभग 1.30 लाख करोड़ रुपये ज्यादा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के गांव, गरीब, पिछड़े, आदिवासी और ओबीसी समुदाय के कल्याण के लिए लिए 112 योजनाओं की शुरुआत की है, लेकिन कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार इन योजनाओं को नीचे तक नहीं पहुंचने नहीं देती। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में एक ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कंधे-से-कंधा मिलाकर कर्नाटक के ओबीसी समाज के सभी समस्याओं का समाधान करे और यह येदुरप्पा जी ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के क्षेत्र में बस स्टैंड बनाने का काम भी येदुरप्पा जी ने ही किया था।

श्री शाह ने कहा कि हैदराबाद कर्नाटक हैदराबाद और मुंबई के बीच का इलाका है। यदि हैदराबाद-मुंबई के बीच इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बना दिया जाय तो राज्य के लाखों युवाओं को नौकरी मिल सकती है, लेकिन सिद्धारमैया सरकार के पास कोई विजन ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और ओबीसी समाज से अपेक्षा है कि वे कर्नाटक में परिवर्तन का वाहक बनें और राज्य में विकास का मार्ग प्रशस्त करें। ■

पत्र-पत्रिकाओं से...

करवट बदलती राजनीति

पूर्वोत्तर में बीजेपी का एक बड़ी ताकत के रूप में उभरना एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है। इसका न सिर्फ पूर्वोत्तर बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी गहरा असर पड़ेगा। बीजेपी ने त्रिपुरा में लेफ्ट का मजबूत किला ढहा दिया और नगालैंड में शानदार प्रदर्शन किया। हाल तक इसकी कल्पना भी असंभव थी। यह बात सही है कि नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों का अपना कोई मजबूत आर्थिक ढांचा नहीं है, इसलिए वे केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के साथ मिलकर चलने में विश्वास करते रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने उनके साथ एक अलग तरह का रिश्ता बनाया है। मोदी सरकार ने नॉर्थ-ईस्ट पर खासतौर से फोकस किया। खुद प्रधानमंत्री ने वहां की कई यात्राएं कीं। केंद्रीय मंत्रियों का आना-जाना लगातार लगा रहा। वहां के लोकप्रिय नेता किरन रिजिजू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में अहम विभाग सौंपा गया। पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कई बड़ी परियोजनाएं शुरू की गईं, जिनसे वहां की जड़ अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है। इस तरह बीजेपी ने उन राज्यों के अलगाव को काफी कम किया और वहां के लोगों का विश्वास जीता। नॉर्थ-ईस्ट को लेकर केंद्र सरकार की सक्रियता के कारण ही इस बार तीन राज्यों के चुनाव मीडिया में छाए रहे।

—(नवभारत टाइम्स, मार्च 5,2018)

नतीजों के निहितार्थ

तीन राज्यों के चुनाव नतीजे पूर्वोत्तर में भाजपा के जबर्दस्त उभार को रेखांकित करते हैं। दूसरी तरफ, ये चुनाव कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काफी निराशाजनक साबित हुए हैं। त्रिपुरा में माकपा का किला ढह गया, जहां वह ढाई दशक से राज कर रही थी। राज्य की साठ सदस्यीय विधानसभा में भाजपा और आइपीएफटी यानी इंडीजीनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के गठबंधन को तैंतालीस सीटें हासिल हुई। गठबंधन में भाजपा का हिस्सा काफी बड़ा है। त्रिपुरा में भाजपा की ऐतिहासिक सफलता का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि पिछली बार उसे लगभग डेढ़ फीसद वोट ही मिले थे, वहीं इस बार अपनी लड़ी गई इक्वायन सीटों पर उसने तैंतालीस फीसद से अधिक वोट हासिल किए। जबकि माकपा को साढ़े बयालीस फीसद वोट आए। पर ज्यादा अंतर सीटों का है। इन तीन राज्यों में लोकसभा की कुल मिलाकर केवल पांच सीटें हैं, लेकिन इन नतीजों का संदेश बड़ा है, क्योंकि पूर्वोत्तर भाजपा के लिए परंपरागत पैठ वाला क्षेत्र नहीं था। केंद्र की सत्ता में आने के बाद भाजपा ने पूर्वोत्तर में बहुत तेजी से पैर पसारे हैं। इस तरह ये चुनाव परिणाम भाजपा के भौगोलिक विस्तार की भी पुष्टि करते हैं।

—(जनसत्ता, मार्च 6,2018)

भाजपा के विजयी रथ ने पूर्वोत्तर को राष्ट्रीय राजनीति की मुख्यधारा में लाने का काम किया

त्रिपुरा, नगालैंड और मेघालय के चुनाव नतीजों के साथ केवल भाजपा का विजय रथ और तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ ही नहीं दिख रहा है, बल्कि पूर्वोत्तर राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में भी आता नजर आ रहा है। इसके लिए एक बड़ी हद तक श्रेय भाजपा को ही जाता है। उसने राजनीतिक तौर पर अलग-थलग से पूर्वोत्तर को राष्ट्रीय राजनीति की मुख्यधारा में लाने का काम किया। यह पूर्वोत्तर के राज्यों में विशेष ध्यान देने की उसकी रणनीति का भी परिणाम है। उसने इस रणनीति पर 2014 में लोकसभा चुनाव जीतने के साथ ही अमल शुरू कर दिया था। ऐसी चुनावी सफलता के दूसरे उदाहरण मिलना मुश्किल हैं। जहां त्रिपुरा में भाजपा की सफलता अकल्पनीय है वहीं वाम दलों और कांग्रेस की पराजय एक ऐसा आघात है जिसके असर को अन्य विपक्षी दल भी महसूस करेंगे। निःसंदेह भाजपा ने त्रिपुरा और नगालैंड फतह करके आगामी विधानसभा चुनावों के साथ-साथ आम चुनावों के लिए भी वह जरूरी ऊर्जा हासिल कर ली है जो विपक्षी दलों के लिए चुनौती बनेगी, लेकिन अब जब भाजपा का विजय रथ और आगे बढ़ चला है तब उसे लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौती पूरी करने पर और ध्यान देना चाहिए।

—(दैनिक जागरण , मार्च 4,2018)

स्कूट विचार...

मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है; मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है।

— गौतम बुद्ध

मानव प्रकृति में दो प्रवृत्तियां रही हैं एक तरफ क्रोध और लोभ तो दूसरी तरफ प्रेम और त्याग।

— पंडित दीनदयाल उपाध्याय

विकास की नीति बनाते समय नीतिकारों को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उसकी गति असंतुलित न हो। किसी भी भाग की उपेक्षा अंततोगत्वा समाज में अनेक प्रकार के तनाव पैदा करती है। हमें इन सभी चीजों से बचना होगा और समाजानुकूल विकास की नीति और उसकी गति रखनी होगी।

— कुशाभाऊ ठाकरे

प्रस्तुतिः पंकज आनंद

SUBSCRIBE

KAMAL SANDESH

The Hon'ble Prime Minister SHRI NARENDRA MODI becomes Life Time Member of Kamal Sandesh

BECOME PART OF A VIBRANT IDEOLOGICAL MOVEMENT

SUBSCRIPTION DETAILS

Name : .....

Address : .....

.....

..... Pin : .....

Phone : ..... Mobile : (1)..... (2).....

E-mail : .....

SUBSCRIPTION TYPE						
	One Year	₹350/-	☐	Life Time (English or Hindi)	₹3000/-	☐
	Three Years	₹1000/-	☐	Life Time (English+Hindi)	₹5000/-	☐

(DETAIL OF THE PAYMENT)

Cheque/Draft No. :..... Date :..... Bank : .....

Note : * DD/Cheque will be made in favour of "**Kamal Sandesh**"
* Money order and Cash accepted with details

(Subscriber's Signature)

KAMAL SANDESH

SEND YOUR DD/CHEQUE ON THIS ADDRESS

Dr. Mookerji Smruti Nyas, PP-66, Subramania Bharati Marg, New Delhi-110003

Ph.: 011-23381428 **Fax:** 011-23387887 **E-mail:** kamalsandesh@yahoo.co.in

KAMAL SANDESH - DEDICATED TO NATIONAL CAUSE

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर झुंझुनू, राजस्थान में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के कार्यकर्ताओं से बातचीत करते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

झुंझुनू, राजस्थान में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के विस्तार तथा राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ करते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

पुडुचेरी स्थित अरविंदो आश्रम में श्री अरविंदो को श्रद्धांजलि देते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली में 'आयुष्मान भारत' के लांच करने की तैयारियों का जायजा लेते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

कर्नाटक में दावणगेरे रैली से पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को हल भेंट करते भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री बीएस येदुरप्पा और अन्य नेतागण

गुलबर्ग, कर्नाटक में ओबीसी नेताओं की एक बैठक को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

प्रेषण तिथिः (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघरः लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20

त्रिपुरा, नगालैंड और मेघालय की विधान सभा चुनावों में भाजपा की अभूतपूर्व जीत के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करते भाजपा पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यगण

नई दिल्ली स्थित भाजपा केंद्रीय कार्यालय में भाजपा मुख्यमंत्री परिषद् की बैठक के दौरान एक ग्रुप फोटो में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, अन्य वरिष्ठ नेतागण तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री